CERAMIC ACADEMY

Shaping the future...

करेंट अफेयर्स

(दिसम्बर, 2025)

- नॉन-रेजीडेंट राजस्थानी (NRR) पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025
- राजस्थान पर्यटन नीति-2025
- प्रवासी राजस्थानी दिवस-10 दिसंबर
- 'विजय दिवस एट होम' समारोह
- DHRUV 64
- राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार-2025
- शिल्प गुरु एवं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार-2023 एवं 2024
- विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAMG) अधिनियम, 2025
- भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

Click Here Click Here

Vikas Gupta Sir

CERAMIC ACADEMY
Shaping the future...

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषयवस्तु	पेज नं.
1.	राजस्थान समसामयिकी	1–21
2.	अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिकी	22–30
3.	राष्ट्रीय समसामयिकी	31–37
4.	आर्थिक समसामयिकी	38–43
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	44–50
6.	पुरस्कार एवं सम्मान	51–55
7.	खेल समसामयिकी	56–61
8.	विविध समसामयिकी	62–63

CERAMIC ACADEMY

राजस्थान समसामयिकी

3 दिसंबर 2025 – राज्य कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

तीन नई नीतियों का अनुमोदन किया →

➢ नॉन-रेजीडेंट राजस्थानी (NRR) पॉलिसी ऑफ राजस्थान - 2025 →

- उद्देश्य – प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना।
  - # निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान-प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को बढ़ावा देने हेतु बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करना।
- कार्यान्वयन – डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स (DORA) DORA के अंतर्गत राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इस नीति की आवधिक समीक्षा की जाएगी।
- वैधता – राज्य सरकार द्वारा संशोधित, प्रतिस्थापित एवं निरस्त किए जाने तक।
- पाँच रणनीतिक स्तम्भ – 1. गति देना (Accelerate) 4. संचालन करना (Drive)
  2. सेतु बनाना (Bridge) 5. सुनिश्चित करना (Ensure)
  3. उत्सव मनाना (Celebrate)
- प्रावधान –
  - # निवेश संबंधी सभी प्रक्रियाओं के समन्वय हेतु 'एनआरआर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल' स्थापित की जाएगी।
  - # इस सेल में इन्वेस्टमेंट लायजन ऑफिसर्स निवेश प्रस्तावों की निगरानी, प्रवासी मिलन कार्यक्रमों का आयोजन और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
  - # राजस्थान फाउण्डेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कॉर्डिनेटर्स नियुक्त किए जाएंगे, जो निवेश लीड्स की पहचान और राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे।
  - # प्रवासी विशेषज्ञों और व्यावसायिक नेताओं के सहयोग से 'एनआरआर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउन्सिल' गठित होगी, जो नीतिगत सुझाव और सेक्टरवार निवेश रोडमैप तैयार करेगी।
  - # प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' (10 दिसंबर) तथा 'प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स' का आयोजन किया जाएगा।
  - # प्रवासियों के लिए ग्लोबल यूथ कनेक्ट, सेलिब्रेट राजस्थान, डायस्पोरा फॉर डेवलपमेंट जैसे नवाचार किए जाएंगे।
  - # प्रवासी राजस्थानी कार्ड जारी किए जाएंगे।
  - # प्रवासी राजस्थानियों की परेशानियों के निराकरण के लिए एक व्यवस्थित शिकायत निवारण और समन्वय तंत्र स्थापित किया जाएगा।

CERAMIC ACADEMY

➤ राजस्थान पर्यटन नीति-2025 →

- इस नीति में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन, पर्यटन अवसंरचना के विकास, प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी सुधार, स्वच्छता एवं सुरक्षा, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को मजबूत करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा पर्यटन इकाईयों के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने पर बल दिया गया है।
  यह 'राजस्थान पर्यटन नीति-2020' को प्रतिस्थापित करेगी।
- कार्यान्वयन-
  # राज्य स्तरीय समिति - राजस्थान पर्यटन बोर्ड के अंतर्गत गठित।
  # नीति क्रियान्वयन इकाई (PIU)- पर्यटन विभाग के अंतर्गत निदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में गठित। यह राज्य स्तरीय समिति को रिपोर्ट करेगी।
- वैधता- अगली नीति जारी होने तक लागू रहेगी।
  # दो वर्ष बाद इस नीति की व्यापक समीक्षा की जाएगी।
- प्रावधान-
  # पर्यटन विभाग 'राज्य वार्षिक पर्यटन पुरस्कार' शुरू करेगा।
  # राज्य के चुनिंदा जिलों में 'मॉडल पर्यटन प्रशिक्षण एवं कौशल केंद्र' स्थापित किए जाएँगे।
  # 10 प्रमुख विरासत पर्यटन स्थलों को 'आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे-जैसलमेर किला, शेरगढ़ किला (बारां), खंडार किला (सवाई माधोपुर), आमेर एवं नाहरगढ़ (जयपुर), किशोरी महल (भरतपुर) आदि।
  # यूनेस्को मान्यता प्राप्त जयपुर परकोटा क्षेत्र के लिए 'विरासत विकास योजना' तैयार की जाएगी।
  # जैसलमेर के तनोट माता मंदिर और लोंगेवाला वॉर म्यूजियम को 'शौर्य पर्यटन सर्किट' में शामिल किया जाएगा।
  # पैनोरमा परियोजनाएं- हड़बूजी (फलौदी) एवं रैवासा धाम (सीकर)
  # शिल्पग्राम की स्थापना- जोधपुर एवं डूंगरपुर
  # शिल्प संग्रहालय- 1. जयपुर - ब्लू पॉटरी 2. कोटा/उदयपुर - मिनिएचर आर्ट 3. बाड़मेर/जोधपुर - लकड़ी का फर्नीचर 4. नाथद्वारा - पिछवाई पेंटिंग
  # म्यूजियम- 1. अल्बर्ट हॉल म्यूजियम (जयपुर) 2. वॉर म्यूजियम (जैसलमेर) 3. वीर बालिका कालीबाई म्यूजियम (उदयपुर)
  # ग्रामीण पर्यटन स्थलों का विकास- 1. बरौली धौं (कामां-डीग) 2. देवमाली (ब्यावर) 3. पिपलान्त्री (राजसमंद) 4. महनसर (झुंझुनू) 5. भूरी पहाड़ी (सवाई माधोपुर) 6. कैमला (बूंदी) 7. रूसी रानी महल (अलवर) 8. आमानेरी (दौसा) 9. शेरगढ़ (बारां) 10. लापोड़िया (टोंक)
  # जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 'जिला पर्यटन विकास समिति' गंतव्य प्रबंधन संगठन के रूप में कार्य करेगी।
  # प्रत्येक जिले का 'पर्यटन मास्टर प्लान' तैयार किया जाएगा।
  # पर्यटन स्थलों के जिर्णोद्धार, संचालन और प्रबंधन हेतु राज्य सरकार 'अडॉप्ट अ टूरिज्म साइट' योजना लागू करेगी।

CERAMIC ACADEMY

राज्य सरकार द्वारा ₹ 5000 करोड़ के 'राजस्थान पर्यटन अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण कोष' की स्थापना की गई है।

- MSME मानक पैकेज– कर्मचारी प्रशिक्षण की कुल लागत का 50% तक एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में 6 महीने के लिए अधिकतम प्रतिपूर्ति–

सूक्ष्म इकाईयों के लिए	लघु इकाईयों के लिए	मध्यम इकाईयों के लिए
₹ 20000 प्रतिमाह	₹ 30000 प्रतिमाह	₹ 40000 प्रतिमाह

- सामान्य विशेषताएँ–
  - # नीति में धार्मिक पर्यटन मार्गों का विकास, वन एवं धार्मिक क्षेत्रों के आस-पास पर्यटन हब की स्थापना, शौर्य सर्किट, बर्ड वाचिंग सर्किट, प्रोजेक्शन मैपिंग एवं लाइट-साउंड शो, प्रीपेड टैक्सी बूथ, ई-व्हीकल टूर, राजस्थान ट्रैवल कार्ड, होम स्टे एवं पेइंग गेस्ट सुविधाओं को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान किए गए हैं।
  - # नीति में चयनित जिलों में विशेष पर्यटन क्षेत्र (STZ) का विकास, पर्यटन परियोजनाओं की अनुमति के लिए सिंगल वेब पोर्टल, पीपीपी के तहत पर्यटन प्रोजेक्ट्स का विकास, स्किलिंग सेंटर्स की स्थापना, पर्यटन छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, सांस्कृतिक विरासत एवं स्थानीय क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए क्राफ्ट म्यूजियम, नए पर्यटन पोर्टल, मोबाइल एप एवं डिजिटल संग्रहालयों का विकास, एयर कनेक्टिविटी के लिए वाइबिलिटी गैप फंडिंग, प्रमुख मेलों एवं उत्सवों का वृहद स्तर पर आयोजन, एस्ट्रो टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कलनरी टूरिज्म, बड़े मनोरंजन प्रोजेक्ट्स तथा वेलनेस टूरिज्म के उन्नयन जैसे उपाय शामिल हैं।
  - # टूरिज्म सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 24×7 कॉल सेंटर, टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स, पेनिक बटन आधारित सुरक्षा प्रणाली, सीसीटीवी और फीडबैक भी इस नीति में शामिल है।

➢ राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 →

- उद्देश्य– बड़े ट्रेड, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे समान अवसर छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराना।
- यह नीति राज्य में 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार को ध्यान में रखते हुए व्यापार क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन करने, छोटे ट्रेडर्स को बाजार एवं ऋण तक आसान पहुँच उपलब्ध करवाने तथा खुदरा एवं थोक व्यापार में एमएसएमई उद्यमों के विकास के लिए कार्य करेगी।
- नोडल विभाग– उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
- कार्यान्वयन– आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य कार्यालय
- वैधता– 31 मार्च 2029
- कार्यान्वयन निगरानी– राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (SLEC)
  - ↳ अध्यक्ष- अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग

CERAMIC ACADEMY

- प्रावधान–

ऋण तक बेहतर पहुँच हेतु क्रेडिट गारंटी योजना–क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) द्वारा तैयार। इसके तहत–

- ₹ 10 करोड़ तक के ऋण पर 75% गारंटी कवरेज (बिना जमानत)
- नए सूक्ष्म व्यापारों हेतु ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 5 वर्षों तक CGTMSE गारंटी शुल्क का 50% राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति।

उत्पादन कारकों से संबंधित सब्सिडी–

₹1 करोड़ तक के ऋण पर	₹1-2 करोड़ तक के ऋण पर	महिला, SC-ST एवं दिव्यांग
6% ब्याज अनुदान	4% ब्याज अनुदान	1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान

सूक्ष्म श्रेणी के खुदरा व्यापारियों को 5 वर्षों तक बीमा प्रीमियम का 50% (अधिकतम ₹1 लाख प्रतिवर्ष) प्रतिपूर्ति।

सूक्ष्म व्यापारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क/कमीशन (शिपिंग छोड़कर) का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹50000 प्रतिवर्ष)

इसके तहत 'राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958' के प्रावधानों में शिथिलता लाने की संभावना पर विचार किया जाएगा।

- नकारात्मक सूची– नीति के दायरे से बाहर वाले क्षेत्र–

1. ऑटोमोबाइल डीलर और थोक विक्रेता 2. ईंधन व्यापार 3. मदिरा व्यापार
4. 20 माइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलिथीन थैलियों का व्यापार

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश–2025 के प्रारूप का अनुमोदन→

➤ भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम–2023 की तर्ज पर। इस अध्यादेश के द्वारा 11 अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटाकर उनके स्थान पर पैनल्टी के प्रावधान किए जा रहे हैं।

➤ उदाहरण– राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम– 1961

जयपुर वाटर सप्लाय एण्ड सीवरेज बोर्ड अधिनियम–2018

राजस्थान वन अधिनियम–1953

↳ धारा–26(1)(ए)–

पहले	अब
वन भूमि में मवेशी चराने पर 6 माह कारावास एवं ₹500 जुर्माना	केवल जुर्माना एवं क्षतिपूर्ति

अन्य निर्णय→

➤ मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति की समय-सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। इस हेतु 'राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के नियम, 1996' में संशोधन किया गया है।

➤ किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है।

CERAMIC ACADEMY

30 दिसंबर 2025 – राज्य कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति–2025' का अनुमोदन किया →

- घोषणा – राज्य बजट 2025-26 में
- उद्देश्य – सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उन्हे वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नष्ट करना।
- प्रावधान –
  - इस नीति के तहत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलीटीज (RVSF) की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - सभी स्क्रैपिंग प्रक्रियाएँ वाहन पोर्टल से एकीकृत होंगी, जिससे स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावना समाप्त होगी।
  - 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, फिटनेस या पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदें गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से RVSF को दिए गए वाहन इस नीति के तहत स्क्रैप किए जा सकेंगें।
  - वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग (CVS) जारी किए जाएंगें। ये वाहन पोर्टल पर भी अपलोड किए जाएंगे।
  - COD के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक (अधिकतम ₹ 1 लाख) की छूट दी जाएगी।
  - रजिस्टर्ड स्क्रैपर स्क्रैप किए गए वाहन के चैसिस नंबर के कट पीस को CVS जारी होने की तारीख से 6 माह तक सैफ कस्टडी में रखेंगे। इसके बाद वे इसे अपने क्षेत्र के जिला परिवहन अधिकारी को जमा करेंगे, जहाँ इसे 18 माह तक सैफ कस्टडी में रखा जाएगा।
  - नीति में निवेश को आकर्षित करने के लिए पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट्स के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें प्रारंभिक 20 इकाईयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी,
  - राज्य कर में छूट, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क में रियायत शामिल हैं। रीसाइकिलिंग एवं स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप को 'राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी' के तहत समर्थन देने का प्रावधान किया गया हैं।

'राजस्थान AI एमरल्ड पॉलिसी–2026' का अनुमोदन किया →

- घोषणा – राज्य बजट 2025-26 में
- उद्देश्य – आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केन्द्रित बनाना,
- प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना तथा नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- नीति में AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया हैं।
- नीति के तहत राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।

CERAMIC ACADEMY

पचपदरा रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स परियोजना→

- वार्षिक क्षमता– 9 मिलियन मैट्रिक टन
- रिफाइनरी परियोजना के लिए राज्य सरकार और HPCL के बीच 18 अप्रैल 2017 को एमओयू हुआ था।
- इस परियोजना को 31 अक्टूबर 2022 तक पूरा किया जाना था।
- लागत–

आरंभिक	2 जून 2023		द्वितीय (वर्तमान) संशोधित लागत
₹ 43129 करोड़	₹ 72937 करोड़	+ ₹ 6522 करोड़ →	₹ 79459 करोड़

- HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को 24 जुलाई 2025 को रिफाइनरी की लागत में द्वितीय संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- इस प्रस्ताव का मूल्यांकन भारत सरकार के उपक्रम मेकॉन लिमिटेड द्वारा किया गया।
- 30 दिसंबर 2025 को राज्य कैबिनेट बैठक में इस संशोधित लागत को मंजूरी दी गई।
- HPCL एवं राज्य सरकार के बीच ऋण इक्विटी अनुपात पूर्व की भाँति 2:1 होगा।
- परियोजना में राज्य सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी 26% के अनुसार ₹6886 करोड़ निर्धारित की गई है। बढ़ी हुई लागत के कारण अतिरिक्त अंश पूंजी के रूप में ₹ 565.24 करोड़ का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

'ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव –2025 योजना' को मंजूरी दी→

- उद्देश्य– वाउचर के रूप में ट्रेडेबल एवं रीडिमेबल ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- इस योजना के तहत उद्यमों एवं शहरी स्थानीय निकायों को नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों, सस्टेनेबल बिल्डिंग एवं अवसंरचना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तथा अन्य पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- इस योजना में पात्र निवेशकों को रिप्स–2024 के तहत मिलने वाले ग्रीन इंसेंटिव्स के अतिरिक्त उनके पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी किए जाएंगे।
- ये वाउचर ₹ 1 करोड़ तक के हरित निवेश पर 5% और ₹ 10 करोड़ से अधिक के निवेश पर 10% (अधिकतम ₹ 2.50 करोड़) तक के मूल्य के होंगे।
- शहरी स्थानीय निकायों को भी स्वयं के संसाधनों से वित्तपोषित परियोजनाओं पर इसी अनुरूप ग्रीन वाउचर जारी किए जाएंगे।

अन्य निर्णय→

स्पेशल सिक्योरिटी विंग के कार्मिकों का विशेष भत्ता अब 25%

राज्य विशेष शाखा (स्पेशल सिक्योरिटी विंग) में पदस्थापित कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन का 15% विशेष भत्ता देय है। इसे अन्य राज्यों में मिल रहे विशेष भत्ते को दृष्टिगत रखते हुए 25% किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (राज्य विशेष शाखा में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संशोधित दर को 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट का अनुमोदन

सप्तम राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट गत 2 सितंबर, 2025 को राज्यपाल को प्रस्तुत की गई थी। उक्त अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंषाओं का राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। अब इन सिफारिशों को राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

राजस्थान राजस्व लेखा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2025 का अनुमोदन

राजस्थान राजस्व लेखा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2025 के प्रारूप को भी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। नवीन सेवा नियमों के लागू होने से राजस्व लेखा संवर्ग के तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर भर्ती होने वाले कार्मिकों को सहायक राजस्व लेखा अधिकारी ग्रेड-2, सहायक राजस्व लेखा अधिकारी ग्रेड-1 के अधीनस्थ सेवा के पदों एवं राजस्व लेखाधिकारी के पद पर राज्य सेवा में पदोन्नति के समुचित अवसर अनुभव एवं पात्रता अनुसार क्रमबद्ध रूप से प्राप्त हो सकेंगे।

राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम-1992 में संशोधन

राजस्थान विधानसभा सचिवालय में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल एवं उप मार्शल के पदों को अब राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त सैन्य एवं अर्द्धसैन्य बलों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण अथवा विशेष चयन के माध्यम से भी भरा जा सकेगा। इसके लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 में संशोधन की कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधित प्रावधानों के तहत मार्शल, अतिरिक्त मार्शल एवं उप मार्शल के पदों पर क्रमशः राजस्थान पुलिस सेवा के एल-19, एल-16 एवं एल-14 पे लेवल के अधिकारियों अथवा सैन्य एवं अर्द्ध सैन्य बल सेवा के एक पे लेवल कम या समकक्ष पे लेवल के 45 वर्ष से कम आयु के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण अथवा विशेष चयन के माध्यम से भर्ती की जाएगी। सहायक मार्शल के पद के लिए राजस्थान अधीनस्थ पुलिस सेवा से उप निरीक्षक पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा राजस्थान विधानसभा सचिवालय में कम से कम एक वर्ष तक लगातार कार्य करने का अनुभव अनिवार्य किया गया है।

CERAMIC ACADEMY

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण

- राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए–

12 दिसंबर– 'नवाचार दिवस–स्टार्टअप कॉन्क्लेव' (जयपुर– राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर)

- विभाग– सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरीशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान (OTS), जयपुर से 50 विकास रथों को रवाना किया।
  - ये आमजन को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे।
  - सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 विकास रथ भेजे गए हैं।

13 दिसंबर– सड़क सुरक्षा अभियान का राज्य स्तरीय समारोह (जयपुर)

14 दिसंबर– राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम– जल महल, जयपुर

15 दिसंबर– 'नव उत्थान, नई पहचान–बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान' थीम पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन – मुख्यमंत्री द्वारा–जवाहर कला केन्द्र, जयपुर (18 दिसंबर तक)

↳ इसी थीम पर राज्य में तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

- RUHS में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारम्भ किया। (लागत- ₹20 करोड़)
- राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर– RUHS प्रतापनगर (जयपुर)
  - प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों एवं सब सेंटरों पर आयोजित किए जा रहे हैं।
  - इनमें 30 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति की बीएमआई, बीपी, शुगर और कॉमन कैंसर आदि की नि: शुल्क जाँच कर नि: शुल्क दवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
  - मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स मोड पर 11 मदर लैब एवं 400 स्पोक्स का शुभारंभ किया।
  - 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के तहत नि: शुल्क जाँचों हेतु राज्य में हब एवं स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है।
  - राज्य में कुल 42 मदर लैब, 137 हब लैब एवं 1377 स्पोक्स चिन्हित किए गए हैं।

Note:– 1–15 दिसंबर तक 894 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य रक्तदान शिविर आयोजित हुए।

- कुल रक्तदाता–44705
- कुल संग्रहित रक्त–44705 यूनिट (सर्वाधिक–कोटा संभाग 16161 यूनिट)

16 दिसंबर– ग्रामीण समस्या समाधान शिविर– लूणकरणसर (बीकानेर)

- मुख्यमंत्री ने ₹612 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं ₹107 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
- पुस्तक विमोचन– 1. बीकानेर जिले की विकास पुस्तिका 2. ग्रामीण सेवा शिविर की सफलता की कहानी 3. शहरी सेवा शिविर–2025

CERAMIC ACADEMY

17 दिसंबर– ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर – आहोर (जालौर)

- मुख्यमंत्री ने ₹ 338 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।
- इसके तहत केशवाना के राजकीय कृषि महाविद्यालय और रानीवाड़ा, चित्तलवाना एवं सांचौर के राजकीय महाविद्यालयों के भवनों तथा हेमागुढ़ा में 33/11 केवी सब स्टेशन और
- पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट-सी के तहत 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों का लोकार्पण किया।
- ₹ 237 करोड़ से अधिक के सड़क उन्नयन सहित विभिन्न विकास कार्यों की नींव रखी।
- इसमें पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट- ए के तहत 19 सौर ऊर्जा संयंत्रों तथा कंवला में 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण शामिल है।

18 दिसंबर– हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव

- मुख्यमंत्री ने जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में 'सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले' का शुभारंभ किया।
- अवधि– 4 जनवरी तक ; आयोजक– राजीविका ; थीम– 'भारत एक सूत्रधार'
- राजस्थान सहित 24 राज्यों की लगभग 300 स्टॉल लगाई गई हैं।

19 दिसंबर– राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन – पंचगांव (धौलपुर)

- मुख्यमंत्री द्वारा राशि हस्तांतरण एवं वितरण–
  - सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को ₹ 1100 करोड़
  - पालनहार योजना के तहत 595000 विद्यार्थियों को ₹ 103 करोड़
  - मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5000 विद्यार्थियों को ₹ 2.5 करोड़
  - अनुसूचित जाति व जनजाति के 155000 छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ₹ 15 करोड़
  - राजस्थान महिला निधि द्वारा 5000 लखपति दीदी को ₹ 100 करोड़ की ऋण सहायता
  - लखपति दीदी, कृषि सखियों और पशु सखियों को टैबलेट वितरण
- आयुषमान आरोग्य योजना के तहत 'आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी' लागू की गई है। इससे प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।

21 दिसंबर– राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम – OTS जयपुर

- मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों को टैबलेट वितरित किए।
- अमर जवान ज्योति, जयपुर से 'रन फॉर विकसित राजस्थान' को रवाना किया।

22 दिसंबर– महिला सशक्तिकरण सम्मेलन – दुधालिया (झालावाड़)

- मुख्यमंत्री ने दुधालिया गांव में महिलाओं द्वारा संचालित गौशाला, बायोगैस प्लांट एवं मियावाकी उद्यान का लोकार्पण किया।
- 5 दिव्यांगजनों को स्कूटी एवं 10 स्कूली बालिकाओं को साइकिल वितरित की।
- डग में स्थित पशु अनुसंधान केंद्र में स्वदेशी गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। (लागत– ₹ 15 करोड़)
- डग चौमहला क्षेत्र में छोटी कालीसिंध नदी पर बांध बनाने के लिए DPR तैयार करने की घोषणा की।

CERAMIC ACADEMY

23 दिसंबर – राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन – मेड़ता (नागौर)

- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राशि हस्तांतरण
  - कृषक कल्याण योजनाओं के तहत 35800 किसानों को ₹187.60 करोड़ की राशि हस्तांतरित की।
  - 5 लाख कृषकों को कृषि आदान अनुदान के रूप में ₹617.58 करोड़
  - मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को ₹150 करोड़
  - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 18500 लाभार्थियों को ₹100 करोड़
- नागौर जिले में ₹300 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत चालू वित्त वर्ष के पहले बैच में 3200 कि.मी. से अधिक की 1216 सड़कों एवं एक पुल के लिए ₹2089 करोड़ के कार्यों का स्वीकृति पत्र सौंपा।

24 दिसंबर – रामगढ़ (सीकर) में कार्यक्रम

- सीकर में ₹155 करोड़ तथा झुंझुनूं में ₹384 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।
- 'फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2025' जारी।

25 दिसंबर – रोजगार मेला (वाणिज्य महाविद्यालय, जयपुर)

- आयोजक – कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

'फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2025' →

- जारी – 24 दिसंबर 2025
- वैधता – 31 मार्च 2029
- नोडल एजेंसी – फिल्म फेसिलिटेशन सेल
  - ↳ अध्यक्ष – पर्यटन विभाग के निदेशक / आयुक्त
- यह नीति राज्य को फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी।
- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क / फीस (अधिकतम 5 दिन) की 100% प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
- राजस्थान में फिल्माई गई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को अधिकतम ₹1 करोड़ तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम ₹50 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- छात्रवृत्ति योजना – निम्नलिखित संस्थानों में अध्ययन या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान निवासी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी –
  1. फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पूणे
  2. सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता
  3. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD), नई दिल्ली
  - प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को चयनित कर अधिकतम ₹50000 की 100% ट्यूशन फीस सहायता एवं ₹5000 प्रतिमाह तक 100% स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।

CERAMIC ACADEMY

➤ सब्सिडी के लिए प्रावधान–

- राजस्थान की लोकेशन को 5-15%, 16-30% और 30% से अधिक स्क्रीन-टाइम देने पर क्रमशः 10%, 20% और 30% सब्सिडी मिलेगी।
- फीचर फिल्म के 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में करने और न्यूनतम व्यय सीमा पूरी करने पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी मिलेगी।
- 100% शूटिंग राजस्थान में करने पर अधिकतम सब्सिडी सीमा के अन्दर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी।

➤ सभी सब्सिडी प्राप्त फिल्मों के लिए राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना अनिवार्य होगा।

➤ थिएटर में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन, राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं की फिल्मों को 100 स्क्रीन पर रिलीज करना अनिवार्य होगा।

➤ पर्यटन विभाग राज्य की सभी शूटिंग लोकेशन्स की विस्तृत डायरेक्टरी तैयार करेगा। साथ ही, एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।

प्रवासी राजस्थानी दिवस – 10 दिसंबर

PRAVASI RAJASTHANI DIVAS
10 DEC 2025 • JAIPUR

➤ आयोजन – JECC सीतापुरा, जयपुर
➤ संस्करण – पहला
➤ कुल पंजीकृत प्रवासी राजस्थानी – 8738
➤ आयोजक – राजस्थान फाउण्डेशन, ब्यूरो ऑफ इंवेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) एवं RIICO
➤ इंडस्ट्री पार्टनर – CII (Confederation of Indian Industry)
➤ 8 विशेष सत्र – 1. प्रवासी राजस्थानी संवाद 2. नवीन एवं अक्षय ऊर्जा 3. उद्योग 4. स्वास्थ्य 5. शिक्षा 6. पर्यटन 7. जल संसाधन 8. खनन
➤ मुख्यमंत्री ने राजस्थान फाउण्डेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा की।

9 विदेशों में

5 देश के विभिन्न राज्यों में

- अब राजस्थान फाउण्डेशन के कुल चैप्टर – 40

CERAMIC ACADEMY

- वर्ष 2026 में 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट' के आयोजन की घोषणा की।
- पिछले वर्ष हुई राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हुए ₹ 35 लाख करोड़ के एमओयू में से ₹ 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई।
- उद्घाटन सत्र में कॉफी टेबल बुक 'कमिटमेंट इन एक्शन' का विमोचन किया गया। इसमें 'राइजिंग राजस्थान' के तहत हुए एमओयू की प्रगति और ग्राउंड ब्रेकिंग की जानकारी शामिल है।
- वेदांता ग्रुप के चैयरमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाने की घोषणा की।
- राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयोजन स्थल पर 'प्रगति पथ' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- 'नॉन-रेजीडेंट राजस्थानी (NRR) पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025' जारी की गई।
- डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफैयर्स (DORA) का गठन किया गया।
- 'प्रवासी राजस्थान सम्मान'- 9 प्रवासी विभूतियों को सम्मानित किया गया।
  1. अनिल अग्रवाल 2. पूनमचंद राठी 3. विनीत मित्तल 4. अजय पिरामल 5. प्रदीप राठौड़
  6. माधव सिंघानिया 7. नरसी कुलरिया 8. सी.एम. मूंदड़ा 9. कुमार मंगलम बिड़ला

प्रदेश में पहली बार वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था लागू

- राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने 'ग्रिड इंटरएक्टिव डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम्स तृतीय संशोधन विनियम- 2025' अधिसूचित किए थे।
- राजस्थान डिस्कोम ने 30 दिसंबर 2025 को इसकी क्रियान्विति के दिशा-निर्देश जारी किए।
- इससे प्रदेश में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया है।
- इसका लाभ मल्टी स्टोरी तथा अपार्टमेंट में रह रहे लोगों, गांव-ढाणी में बसे लोगों, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा 1 मेगावाट क्षमता तक विद्युत भार वाले वृहद उद्योगों एवं ऐसे अन्य उपभोक्ताओं को होगा, जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है, जिससे वे व्यक्तिगत रूप से सोलर नहीं लगा पाते।
- उपरोक्त विनियमों के तहत 10 किलोवाट तक की घरेलू सोलर परियोजनाओं को बिना तकनीकी अध्ययन के स्वीकृत माना जाएगा।
- 10 किलोवाट से अधिक विद्युत भार वाली सोलर परियोजनाओं के लिए तकनीकी अध्ययन की समय सीमा → मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए - 15 दिन
  → नए उपभोक्ताओं के लिए - 30 दिन
- घरेलू उपभोक्ताओं को व्हीलिंग चार्ज, बैंकिंग चार्ज और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज से पूरी छूट दी गई है।

वर्चुअल नेट मीटरिंग

वर्चुअल नेट मीटरिंग ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक स्थान पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न होने वाली बिजली को उसी डिस्कॉम क्षेत्र में आने वाले कई उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में समायोजित किया जाता है।

- उदाहरण के लिए, किसी अपार्टमेंट, कॉलोनी या संस्थान के पास स्वयं की छत नहीं है अथवा सीमित स्थान है तो वे किसी अन्य स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर वहां से उत्पन्न बिजली का लाभ अपने-अपने मीटरों में प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रुप नेट मीटरिंग

इसमें उपभोक्ता एक स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है तो उससे उत्पन्न बिजली को उसी डिस्कॉम क्षेत्र के तहत आने वाले उसके अन्य कनेक्शनों में समायोजित किया जा सकता है।

- उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता के पास घर, दुकान, ऑफिस अथवा अन्य कोई संस्थान एक स्थान पर सोलर संयंत्र लगाकर वहां से उत्पन्न बिजली का उपभोग अपने अन्य स्थानों के विद्युत कनेक्शन पर भी कर सकता है।
- इसका सर्वाधिक लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को होगा, जिनके कई संस्थान हैं और वहां उनके अलग-अलग बिजली कनेक्शन हैं। जैसे- स्कूल, अस्पताल, चैरिटेबल संस्थान आदि।

उपभोक्ताओं को लाभ

इससे घरेलू उपभोक्ताओं को सभी तरह के शुल्कों से पूरी तरह छूट मिलेगी। घरेलू के अलावा अन्य उपभोक्ताओं को भी कई शुल्कों से राहत मिलेगी। विशेषकर रेस्को मॉडल में अधिभार सामान्य ओपन एक्सेस दरों के 50% पर होगा।

- बैटरी एनर्जी स्टोरेज से जुड़ी परियोजनाओं पर भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा और 5% बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली क्षमता पर व्हीलिंग चार्ज से 75% तथा 30% से अधिक बैटरी ऊर्जा भण्डारण क्षमता पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।
- साथ ही, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राज्य सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक रूफ टॉप सोलर लगाने का है। इसके लिए आवेदन शुल्क, सिक्योरिटी डिपोजिट, मीटर परीक्षण शुल्क एवं एग्रीमेंट में भी छूट दी गई है।

CERAMIC ACADEMY

41 जिलों में पंचायतों का पुनर्गठन →

- अधिसूचना – 21 नवंबर 2025

	पहले	अब	नवगठित
ग्राम पंचायतें	11194	14635	3441
पंचायत समितियाँ (33 जिलों में)	–	85	450
जिला परिषद	33	41	8

- नवगठित ग्राम पंचायतें → सर्वाधिक – बाड़मेर (270 पंचायतें)
  → न्यूनतम – झालावाड़ (19 पंचायतें)
- सर्वाधिक नवगठित पंचायत समितियाँ – जोधपुर (7)
- 8 जिलों में पंचायत समितियाँ गठित नहीं की गई – झालावाड़, भरतपुर, डीग, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ एवं पाली।
- नाम परिवर्तन → नगर पंचायत समिति (डीग) – ब्रज नगर पंचायत समिति
  → सम पंचायत समिति (जैसलमेर) – खुहड़ी पंचायत समिति
- समाप्त पंचायत समितियाँ – 1. सीकरी (डीग) 2. भनोखर (अलवर)

पंचायतीराज एवं शहरी निकाय चुनाव की खर्च सीमा में वृद्धि →

- यह खर्च सीमा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बढ़ाई गई है।

पंचायतीराज	पहले	अब (दोगुना)	शहरी निकाय	पहले	अब
जिला परिषद् सदस्य	₹1.5 लाख	₹3 लाख	नगर निगम पार्षद	₹2.50 लाख	₹3.50 लाख
पंचायत समिति सदस्य	₹75 हजार	₹1.5 लाख	नगर परिषद पार्षद	₹1.5 लाख	₹2 लाख
सरपंच	₹50 हजार	₹1 लाख	नगर पालिका पार्षद	₹1 लाख	₹1.5 लाख

पंचायतीराज चुनाव वार्ड संख्या निर्धारण →

- राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं में वार्ड निर्धारण हेतु नवीन मापदण्ड जारी किए –

	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
आबादी	3000	1 लाख	4 लाख
वार्ड संख्या	7	15	17
	प्रति 1000 आबादी पर 2 अतिरिक्त वार्ड	प्रति 15000 आबादी पर 2 अतिरिक्त वार्ड	प्रति 1 लाख आबादी पर 2 अतिरिक्त वार्ड

लोकायुक्त →

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 24 दिसंबर को लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर के लोगो का अनावरण किया।
ध्येय वाक्य – 'न्यायो नीतिः च शासनम्'

राज्य में 'राजभवन' का नाम बदलकर अब 'लोकभवन' कर दिया गया है।

- अधिसूचना – 1 दिसंबर 2025 (राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा)

CERAMIC ACADEMY

5 दिसंबर को साधुवाली (श्रीगंगानगर) में गंगनहर शताब्दी समारोह के अवसर पर नहरी तंत्र के लिए ₹1717 करोड़ के कार्यों की सौगात दी→

- ₹ 300 करोड़ – बीकानेर कैनाल का पुनरूद्धार
- ₹ 695 करोड़ – गंगनहर प्रणाली के 3.14 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का ऑटोमेशन
- ₹ 647.62 करोड़ – फीरोपुर फीडर का पुनर्निर्माण
- फीरोपुर फीडर का पुनर्निर्माण→
  - 5 दिसंबर, 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शिलान्यास।
    - ↳ 5 दिसंबर, 1925 को महाराजा गंगासिंह ने गंगनहर का शिलान्यास किया था।
  - घोषणा– बजट वर्ष 2024-25 (₹200 करोड़)
  - कुल लागत– ₹647.62 करोड़
    - राजस्थान – ₹268.50 करोड़
    - पंजाब – ₹379.12 करोड़

  - इन पुनर्निर्माण कार्यों से हरिके बैराज में आने वाले अधिक पानी को फीरोपुर फीडर में लाया जाएगा जिससे गंगनहर में वर्षभर पर्याप्त पानी रहेगा।
  - गंगनहर के 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के काश्तकार लाभान्वित होंगे।
  - ये पुनर्निर्माण कार्य अक्टूबर 2027 तक पूरे किए जाएंगे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गन्ने के वर्तमान समर्थन मूल्य में ₹15 प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की।

दुग्ध उत्पादन→

- प्रसंस्करण क्षमता को 48 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 54 लाख लीटर प्रतिदिन हो गयी है।
  - ↳ लक्ष्य – अगले दो वर्ष में 70 लाख लीटर प्रतिदिन करना।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) द्वारा ₹ 1000 करोड़ का फंड गठित कर निम्नलिखित जिलों के दुग्ध संयंत्रों का उन्नयन प्रारम्भ किया गया है–
  1. कोटा 2. भरतपुर 3. अलवर 4. उदयपुर 5. जोधपुर

Note– राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन पशुधन की आनुवांशिक गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत नरवा और बस्सी स्थित दो सीमन सेंटरों का उन्नयन कर रहा है।

स्वर्ण खनन नीलामी→

- दो स्थलों पर– 1. कांकरिया (बांसवाड़ा)
  2. डगोचा (सलूम्बर)

CERAMIC ACADEMY

नौनेरा वृहद एवं परवन अकावद पेयजल परियोजना →

➢ राज्य सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' के तहत इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

	नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना	परवन अकावद पेयजल परियोजना
व्यय	₹ 1661.14 करोड़	₹ 3523.16 करोड़
लाभ	कोटा एवं बून्दी जिलें के 749 गाँव तथा 6 कस्बों के 113287 परिवार।	झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों के 1402 गाँव एवं 276 ढाणियाँ।
निर्माण कार्य	1 इन्टेक पंप गृह, 3 जल शोधन संयंत्र, 14 स्वच्छ जलाशय तथा 137 उच्च जलाशय निर्माण। 58.45 कि.मी. लंबी रॉ वाटर राइजिंग मैन पाइपलाइन। नौनेरा वृहद परियोजना से 4506.89 कि.मी. लंबी राइजिंग मैन, क्लस्टर वितरण एवं ग्रामीण वितरण पाइपलाइन। कुल 14 पंप गृह निर्माण।	कोटा एवं झालावाड़ जिलें के लिए 2 इन्टेक पंप गृह निर्माण, 2 जल शोधन संयंत्र, 41 स्वच्छ जलाशय तथा 276 उच्च जलाशय। झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों के लिए 661 कि.मी. लंबी मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन। परवन अकावद पेयजल परियोजना से 9477 कि.मी. लंबी राइजिंग मैन, क्लस्टर वितरण एवं ग्रामीण वितरण पाइपलाइन।
दोनों परियोजनाओं को अगस्त 2027 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।		

प्रमुख सेंटर एवं केन्द्र

अटल ज्ञान केन्द्र →

➢ घोषणा – 25 दिसंबर 2024 (सुशासन दिवस पर)

➢ ग्राम पंचायत स्तर पर इनकी स्थापना की जाएगी।

➢ प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी गई है।

➢ अब तक 1274 केन्द्र चिन्हित कर उनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

➢ केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्गठित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' के तहत राजस्थान के लिए 1047 पंचायत लर्निंग सेंटर (PLC) की स्वीकृति प्रदान की गई है। (राशि – ₹ 232 करोड़ से अधिक) यह स्वीकृति अटल ज्ञान केन्द्रों को सुदृढ़ करने में सहायक होगी।

➢ विशेषताएं –

- इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है।
- प्रत्येक केन्द्र में ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जहाँ पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्री डिजिटल रूप में मौजूद रहेगी।
- करियर परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी इस केन्द्र का हिस्सा होंगे।
- साथ ही, ई-मित्र और कॉमन सर्विस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगें।
- प्रत्येक केन्द्र में एक प्रशिक्षित 'अटल प्रेरक' नियुक्त किया जाएगा। यह प्रेरक एक स्थानीय युवा होगा।

CERAMIC ACADEMY

राज्य स्तरीय डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर →

- घोषणा – राज्य बजट 2024-25 में
- स्थापना – ओद्यपुर
  - इसके लिए ग्राम लोरडी पंडितजी में 25 हजार वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई हैं।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन →

- घोषणा – राज्य बजट 2025-26 में
- स्थापना – जगतपुरा (जयपुर)
- यह राज्य में अपनी तरह का पहला ऐसा केन्द्र होगा।
- इसके गठन की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल को दी गई हैं।
- नॉलेज पार्टनर – IIT ओद्यपुर

हाइटेक साइबर फ्यूजन सेंटर →

- केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देशभर में ऐसे 20 सेंटर बनाए जा रहे हैं।
- राजस्थान में इसके लिए 5 पुलिस जिलों का चयन किया गया हैं –
  1. भिवाड़ी 2. अलवर 3. खैरथल-तिजारा 4. डीग 5. सवाई माधोपुर

वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर →

- स्थापना – ओद्यपुर
- लागत – ₹ 18 करोड़
- केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा हैं।

पर्यावरण

रामसर साइट →

- भारत के दो स्थल रामसर साइट में शामिल –
  1. कोपरा जलाशय (छत्तीसगढ़) – 95 वीं
  2. सीलीसेढ़ झील (राजस्थान) – 96 वीं
- घोषणा – 12 दिसंबर
- अब राजस्थान में कुल 5 रामसर स्थल हो गए।
- अब भारत में कुल 96 रामसर स्थल हो गए।
  - 1st – तमिलनाडु – 20
  - 2nd – उत्तरप्रदेश – 10
- विश्व में
  - 1st – यूनाइटेड किंगडम – 176
  - 2nd – मैक्सिको – 144
  - 3rd – भारत – 96 (एशिया में सर्वाधिक)

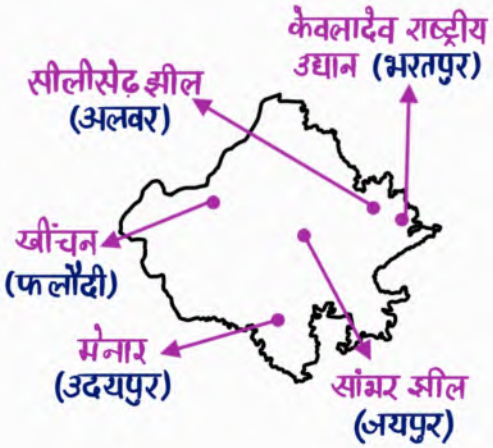

CERAMIC ACADEMY

अरावली की नई परिभाषा →

- सुर्पीम कोर्ट ने 'Issue Relating to Defination of Aravali Hills and Ranges' नाम से अरावली के संबंध में निर्देश जारी किए।
- निर्णय– बी. आर. गवई (20 नवंबर 2025)
- सुर्पीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित समिति की अरावली पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार किया।
- अरावली पहाड़ी– अरावली जिलें में स्थित कोई भी भू-आकृति, जिसकी स्थानीय भू-आकृति से ऊँचाई 100 मीटर या उससे अधिक हैं।
- अरावली पर्वत श्रृंखला– दो या दो से अधिक अरावली पहाड़ियाँ, जो एक-दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित हो, अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती हैं।
- अरावली गुजरात, राजस्थान एवं हरियाणा के कुल 37 जिलों में विस्तृत हैं।
- सुर्पीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देशित किया कि, वह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की मदद से अरावली के लिए 'सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान' तैयार करे।
- जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 दिसंबर 2025 को सुर्पीम कोर्ट के उपर्युक्त निर्णय पर रोक लगा दी।

Note:– सुर्पीम कोर्ट के उपर्युक्त निर्णय से पूर्व केवल राजस्थान ही अरावली क्षेत्र में खनन विनियमन के लिए औपचारिक रूप से स्थापित परिभाषा का प्रयोग कर रहा था।

- परिभाषा – स्थानीय भू-आकृति से 100 मीटर ऊँचाई पर उठने वाली सभी भू-आकृतियाँ।
- लागू– 9 जनवरी 2006
- यह परिभाषा राज्य सरकार की 2002 की समिति रिपोर्ट पर आधारित हैं।
- यह परिभाषा 'रिचर्ड मर्फी भू-आकृति वर्गीकरण' के आधार पर निर्धारित की गई हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) →

- सुर्पीम कोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के संबंध में एक निर्णय दिया।
- निर्णय– जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा व अतुल एस. चंदुरकर की पीठ द्वारा
- केस– एम. के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ।
- प्रमुख निष्कर्ष–
  - कोर्पोरेट सोशल रिस्पोंसबिलिटी (CSR) में अंतर्निहित रूप से 'पर्यावरणीय उत्तरदायित्व' शामिल है।
  - पर्यावरण संरक्षण के लिए CSR कोष एक संवैधानिक कर्तव्य है, न कि स्वैच्छिक परोपकारी कार्य।

Corporates have fundamental duty to protect the ecosystem, asserts SC

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday interpreted 'corporate social responsibility' or CSR to inherently include environmental responsibility, holding that the legal person of a corporation has a fundamental duty to protect the environment as *a key organ* of society.

"The corporate duty must evolve from merely protecting the shareholders to protecting the ecosystem that we all inhabit. Therefore, the corporate definition of 'social responsibility' must inherently include 'environmental responsibility'," a Bench of Justices P.S. Narasimha and Atul S. Chandurkar held in a judgment.

The judgment was based on petitions highlighting the cause of a near-extinct bird species – the Great Indian Bustard, "one of the heaviest flying birds in the world and a flagship species of the arid and semi-arid grasslands of the Indian subcontinent", primarily located in and around the Great Thar desert.

The court brought companies under the ambit of Article 51A(g) of the Constitution, which imposes a fundamental duty on every citizen "to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures".

"Companies cannot assert to be socially responsible while ignoring equal claims of the environment and other beings of the ecosystem...," Justice Narasimha, who authored the judgment, reasoned.

The court explained that allocation of CSR funds by companies for the protection of the environment cannot be seen as "a voluntary act of charity", but a fulfilment of a Constitutional obligation.

The judgment was in response to petitions on risks faced by the Great Indian Bustard.

Shared environment

"The obligation to protect endangered species is paramount... Where corporate activities such as mining, power generation, or infrastructure threaten the habitat of endangered species, the 'polluter pays' principle mandates that the company bears the cost of species recovery. CSR funds must, therefore, be directed towards ex-situ and in-situ conservation efforts to prevent extinction," the court said.

Non-renewable power generators operating near the habitats of the Great Indian Bustard in Rajasthan and Gujarat must always remember that they share the environment with the bird and must undertake their activities as if they were "guests in its abode", Justice Narasimha said.

The court also upheld an expert committee's recommendations to revise the priority areas to 14,013 sq. km and 740 sq km for Rajasthan and Gujarat, respectively.

CERAMIC ACADEMY

- किसी कंपनी के रूप में विधिक व्यक्ति का समाज के एक प्रमुख अंग के रूप में पर्यावरण की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। (संविधान के अनुच्छेद-51A(g) के तहत)
- गोडावण के लिए प्राथमिक संरक्षण क्षेत्र को संशोधित किया गया है–
  राजस्थान– 14013 वर्ग कि.मी. एवं गुजरात– 740 वर्ग कि.मी.

राजस्थान-मध्यप्रदेश चीता कोरिडोर→

- कॉरिडोर का नाम– 'कूनो- गाँधीसागर चीता लैंडस्केप'
- कुल क्षेत्र– 17000 वर्ग कि.मी.
  - राजस्थान– 6500 वर्ग कि.मी. (37%)
  - मध्यप्रदेश– 10500 वर्ग कि.मी. (63%)
- कॉरिडोर में शामिल राजस्थान के अभयारण्य–

अभयारण्य	जिला	अभयारण्य	जिला
बस्सी एवं भैंसरोडगढ़	चित्तौड़गढ़	रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व	बूंदी
रणथम्भौर	सवाई माधोपुर	करौली- धौलपुर टाईगर रिजर्व	
मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व	कोटा	शेरगढ़ अभयारण्य	बांरा
चंबल घड़ियाल अभयारण्य–	कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर		

योजनाएँ (Schemes)

कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान→

- प्रारंभ– 15 जनवरी, 2025 (सांगानेर, जयपुर)
  - ↳ 41 जिलों की 11195 ग्राम पंचायतों में
- नोडल विभाग– भूजल विभाग
- यह केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय के 'कैच द रेन' अभियान से प्रेरित है।
- लक्ष्य– वर्ष 2027-28 तक 45000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे।
- उद्देश्य– 1. वर्षा जल के संरक्षण को बढ़ावा देना।
  2. भू-जल स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करना।
  3. जल संचय में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
  4. प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों, क्राउड फण्डिंग और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी (CSR) के सहयोग से रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना।
- प्रदेशभर में ग्राम विकास अधिकारियों ने ई-पंचायत मोबाईल एप के माध्यम से 42081 रिचार्ज स्थलों का चयन किया है।
- अभियान के सुचारू संचालन और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय राज्य 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान समिति गठित की गई है।
- विभिन्न विभागों में प्रभावी समन्वय, कन्वर्जेंस, योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण एवं योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय 'राज्य स्तरीय निर्देशन समिति' बनाई गई है।
- जिला स्तर पर जिला क्लेक्टर की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय 'जिला स्तरीय समिति' का गठन किया गया है।

फ्लैगशिप योजना

CERAMIC ACADEMY

सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम→

- प्रारंभ – 20 जून, नई दिल्ली
- मंत्रालय– केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  - शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन (SSEF) के सहयोग से शुरू।
- पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया हैं। पहले चरण में 10 राज्यों के 30 शहरों में प्रारंभ।
- अब इसे देश के 100 शहरों तक विस्तारित किया गया हैं।
- राजस्थान के चार शहर इसमें शामिल हैं– जयपुर,जोधपुर,अजमेर एवं उदयपुर।

शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना→

- घोषणा – राज्य बजट 2025-26 में
- इसके तहत झुंझुनूं, सीकर और चुरू जिलों की 662 हवेलियों को संरक्षण हेतु चिन्हित किया गया हैं।

चर्चित व्यक्तित्व

नियुक्तियां→

- डॉ. तारकेश्वर जैन– राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के चैयरमेन नियुक्त
  - कार्यकाल– 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक
- समित बिश्नोई– राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के उप- सॉलिसिटर जनरल
  - नियुक्ति – केन्द्रीय कानून मंत्रालय द्वारा
  - कार्यकाल– 3 वर्ष
- सुनिल शर्मा – राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त (8 दिसंबर 2025)
  - नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा ; शपथ– मुख्य सूचना आयुक्त एम.एल. लाठर द्वारा
  - कार्यकाल– 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
- शशिकांत – राज्य के मुख्य नगर नियोजक नियुक्त
  - नियुक्ति – नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा
- डॉ. राजेन्द्र बाबू दुबे – राज्यपाल द्वारा 'स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरू नियुक्त।

अन्य व्यक्तित्व→

- मनस्वी अग्रवाल (उदयपुर)– अण्टार्कटिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी 'विन्सन मैसिफ' पर चढाई करने वाली पहली राजस्थानी बनी।
- अंजलि सिंह (झुंझुनू)– नेशनल यूथ पार्लियामेंट–2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

CERAMIC ACADEMY

पुरस्कार एवं सम्मान

डॉ. कोमल कोठारी स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट लोककला पुरस्कार-2025 →

- समारोह - शिल्पग्राम महोत्सव, उदयपुर (21-30 दिसंबर)
- प्रदान करने वाली संस्था - पश्चिमी सांस्कृतिक कला केन्द्र, उदयपुर
- पुरस्कार विजेता - 1. रामनाथ चौधरी (अलगोजा वादक, जयपुर)
  2. निरंजन वल्लभ भाई (गुजरात)

78 वाँ आर्मी डे परेड संयुक्त कर्टन रेजर कार्यक्रम →

- आयोजन - JECRC यूनिवर्सिटी, जयपुर
- 78 वें आर्मी डे परेड का आयोजन 15 जनवरी को जयपुर में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निम्नलिखित की वीरांगनाओं को सम्मानित किया-
  1. मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित नायक मेघ राज सिंह
  2. मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित हवलदार राम सिंह शेखावत
  3. मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित लांस नायक बंशीधर यादव
- निम्नलिखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी सम्मानित किया-
  1. ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित 2. सुबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ 3. हवलदार मदन सिंह काजला

नवंबर-2025 में चेन्नई में आयोजित 'विंड इंडिया-2025 सम्मेलन' में राजस्थान को 'एक्सीलेंस इन विंड एंड हाईब्रिड पॉलिसी पुरस्कार' प्रदान किया गया।

भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने 'राजस्थान पुलिस अकादमी' (RPA) को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा प्रदान किया।

भाविनी भार्गव (जयपुर) - रोटरी इंटरनेशनल यंग अचीवर अवॉर्ड से सम्मानित।

चर्चित स्थान

बीकानेर - राजकीय महारानी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजस्थान का पहला सरकारी विद्यालय होगा जहाँ राजस्थान की पहली अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

जयपुर - जयपुर जिले का पहला राजकीय विधि महाविद्यालय - सांगानेर (सीटें-120)
स्थायी भवन बनने तक संचालन-शहीद पुनीतनाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

दौसा - 8 दिसंबर को मेंहदीपुर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई।

झालावाड़ - गागरोन दुर्ग में 5100 विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी की जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डस में दर्ज किया गया।
- 'पंच गौरव योजना' के तहत यहाँ 'गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव' आयोजित किया गया था।

CERAMIC ACADEMY

सम्मेलन / कार्यक्रम / महोत्सव

	सम्मेलन / कार्यक्रम / महोत्सव	स्थान	आयोजक
1.	सांभर महोत्सव	जयपुर	27-31 दिसंबर
2.	फोरहैक्स फैयर-2025	जयपुर	आयोजक- केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय
3.	राष्ट्रीय हैकथॉन शील्ड 1.0	केन्द्रीय आसूसी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	
4.	राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव	चितौड़गढ़	
5.	राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का प्रदेश शिक्षक सम्मेलन	लियो इंटरनेशनल संस्थान (बांसवाड़ा)	
6.	मारवाड़ महोत्सव	संबलपुर (ओडिशा)	आयोजक- मारवाड़ी युवा मंच
7.	पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव	जोधपुर (26 Dec.-4 Jan.)	आयोजक- लघु उद्योग भारती

'ऑनर रन' मैराथन →

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्बर्ट हॉल (जयपुर) पर थल सेना की दक्षिण-पश्चिम कमान की ओर से पूर्व सैनिकों की वीरता और बलिदान के सम्मान में आयोजित 'ऑनर रन' मैराथन का फ्लैग ऑफ किया। (7 दिसंबर)
- यह मैराथन 'सेना दिवस' (15 जनवरी) के उपलक्ष में आयोजित की गई है।
- यह मैराथन तीन श्रेणियों में आयोजित की गई - 5 कि.मी., 10 कि.मी. एवं 21 कि.मी.।

राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन सम्मान समारोह →

- आयोजन- हरीशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान (OTS), जयपुर
  - 3 दिसंबर - अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (1992 ई. में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित)

आगो, जगाओ एकता पदयात्रा →

- शुभारंभ - 24 नवंबर, 2025 जुलमी ग्राम पंचायत (कोटा) (पाटली नदी के तट पर)
  - डॉ. किरोड़ी लाल मीणा तथा मदनलाल दिलावर द्वारा
- सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती के उपलक्ष में।

सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह →

- आयोजन- रीपा (जयपुर)
- मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाएँ -
  1. सीटी पार्क (जयपुर) में 'अटल काव्य स्मारक' बनवाया जाएगा।
  2. जयपुर में 'अटल लोकतंत्र उपवन' का निर्माण भी किया जाएगा।

CERAMIC ACADEMY

- भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) द्वारा पुनर्वास एवं मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान के चार संस्थाओं को उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) का दर्जा दिया –
  1. एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर
  2. जेएनवीयू विश्वविद्यालय, जोधपुर
  3. एमएलएसयू, उदयपुर
  4. सीआरसी आमडोली, जयपुर

- **राजकॉप सिटीजन एप →**
  - राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा द्वारा शुरू किया गया था।
  - इसमें 'मीड हेल्प' फीचर दिया गया है।

- **लीगल ऑफिसर पोर्टल →**
  - विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा शुभारंभ किया गया।
  - इस पोर्टल से स्थानांतरण प्रक्रिया और विभाग, कार्मिकों के बीच पत्राचार अधिक सरल, पारदर्शी और सुगम हो सकेगा।

- **राज्य स्तरीय स्वच्छता रैंकिंग →**
  - स्वायत शासन विभाग द्वारा जारी की गई–

आबादी	10 लाख से अधिक	3–10 लाख	3 लाख–50 हजार	20–50 हजार	20 हजार से कम
प्रथम स्थान	जयपुर ग्रेटर	भीलवाड़ा	भरतपुर	नाथद्वारा	बड़ी सादड़ी

- पंचायती राज मंत्रालय की AI आधारित 'सुभासार' पहल में राजस्थान का देश में स्थान– 14वाँ

CERAMIC ACADEMY

अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिकी

भारतीय प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएँ

जॉर्डन की यात्रा →

- यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधो की 75 वीं वर्षगांठ पर हुई हैं।
- जॉर्डन के प्रधानमंत्री- डॉ. जफर हसन
- प्रमुख समझौता ज्ञापन →
  1. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग।
  2. जल संसाधन प्रबंधन एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग
  3. पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग व्यवस्था के क्षेत्र में समझौता
  4. वर्ष 2025-29 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण
  5. डिजिटल रूपांतरण के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर आशय पत्र।

इथोपिया की यात्रा →

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ
- इथोपिया' से सम्मानित किया गया।
- इथोपिया के राष्ट्रपति – ताय अत्स्के सैलासी
- प्रमुख परिणाम →
  - द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक उन्नत करना।
  - इथोपिया के विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन।
  - संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों में प्रशिक्षण में सहयोग के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था।
  - G20 साझा प्रारूप के अंतर्गत इथोपिया के संबंध में ऋण पुनर्गठन पर समझौता ज्ञापन।
  - ITEC (Indian Technical Economic Cooperation) कार्यक्रम के अंतर्गत AI के क्षेत्र में इथोपिया के छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष अल्पकालिक पाठ्यक्रम।

ओमान की यात्रा →

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया गया।
- अब प्रधानमंत्री मोदी को कुल 29 देशों के राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।
- यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधो की 70 वीं वर्षगांठ पर हुई हैं।
- प्रमुख परिणाम →
  - कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन के क्षेत्र में फ्रेमवर्क अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट।
  - लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर सहित सामुद्रीक संग्रहालयों के समर्थन हेतु सहयोगात्मक साझेदारी की स्थापना।
  - व्यापक-आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)- विस्तृत जानकारी Deep Dive में दी गई हैं।

CERAMIC ACADEMY

23 वाँ भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन→

- आयोजन– हैदराबाद हाऊस, नई दिल्ली (5 दिसंबर, 2025)
- यह भारत–रूस 'रणनीतिक साझेदारी' की घोषणा की 25 वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया।
- इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन (4–5 दिसंबर, 2025) भारत की यात्रा पर रहे।
- प्रमुख घोषणाएँ→
  1. 'भारत–रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2030 तक का कार्यक्रम
     ↳ लक्ष्य– 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन करना।
  2. रूस ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की।
  3. रूसी नागरिकों को 30 दिन का निःशुल्क ई-पर्यटक वीजा एवं समूह पर्यटक वीजा दिया जाएगा।
- प्रमुख समझौते→
  1. मैसर्स JSC यूराकेलम और मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इंडीयन पोटाश लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।
  2. भारत सरकार के डाक विभाग एवं JSC 'रूसी पोस्ट' के बीच इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस (IETPS) से संबंधित द्विपक्षीय समझौता।
  3. रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान, पूणे और रूस के फेडरल स्टेट ऑटोनोमस उच्च शिक्षा संस्थान 'नेशनल टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी' के बीच समझौता ज्ञापन।
  4. राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली एवं हस्तकला अकादमी और जारित्सिनों स्टेट ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प, कला एवं भूदृश्य संग्रहालय–रिजर्व के बीच प्रदर्शनी 'इंडिया : फेवरिक ऑफ टाइम' के लिए समझौता।

द्विपक्षीय समझौते

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अर्जेंटीना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ने कृषि अनुसंधान, क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी विनिमय में द्विपक्षीय सहयोग के लिए कार्ययोजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए।

- भारत और नीदरलैंड्स ने समझौता ज्ञापन के माध्यम से 'भारत-नीदरलैंड्स संयुक्त व्यापार और निवेश समिति' (JTIC) स्थापना की घोषणा की।
  - नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री– डेविड वान वील

- भारत और नीदरलैंड्स ने लोथल (गुजरात) में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि भारत की संसद सऊदी अरब के साथ संसदीय मैत्री समूह का गठन करेगी।

CERAMIC ACADEMY

ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल-2025 →

- जारीकर्ता – स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी
- यह सूचकांक 36 देशों का मूल्यांकन करता है।

शीर्ष स्थान	USA	चीन	भारत
रैंक (स्कोर)	1 (78·60)	2 (36·95)	3 (21·59)

- भारत की स्थिति –
  - लगभग 33% वार्षिक भर्ती दर के साथ AI प्रतिभा प्राप्त करने में दुनिया में सबसे आगे।
  - वर्ष 2016 से AI प्रतिभा सार में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई।

जलवायु जोखिम सूचकांक-2026 →

- जारीकर्ता – जर्मनवॉच (ब्राजील में आयोजित COP-30 में)
- यह सूचकांक पिछले 30 वर्षों (1995 – 2024) के आँकड़ों पर आधारित है।
- इसमें चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को मापने के लिए 6 प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया गया है।
- प्रमुख निष्कर्ष –
  - दीर्घकालिक अवधि (1995 – 2024) में सर्वाधिक प्रभावित देश – 1. डोमिनिका 2. म्यांमार 3. होंडुरास
  - वर्ष 2024 में सर्वाधिक प्रभावित देश –
    1. सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस 2. ग्रेनेडा 3. चाड़

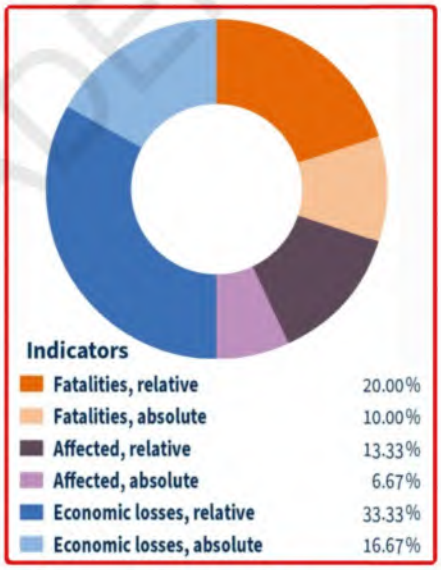

- भारत की स्थिति –
  - पिछले 30 वर्षों (1995 – 2024) में दुनियाँ का 9वाँ सर्वाधिक प्रभावित देश हैं।
  - वर्ष 2024 में आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या के मामलें में तीसरे स्थान पर हैं।

एशिया पावर इंडेक्स-2025 →

- जारीकर्ता – लोवी इंस्टीट्यूट (ऑस्ट्रेलिया)
- संस्करण – 7वाँ
- यह सूचकांक एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों की शक्ति का 8 विषयगत उपायों एवं 131 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन करता है।

शीर्ष स्थान	USA	चीन	भारत	निम्नतम स्थान – पापुआ न्यू गिनी
रैंक	1	2	3	27
स्कोर	80·5	73·7	40·5	4·6

CERAMIC ACADEMY

अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ

	व्यक्तित्व	देश	पद
1.	एलेक्सेन्ड्रे मुंतियानू	मालडोवा	प्रधानमंत्री
2.	म्विगुलु नचेम्बा	तंजानिया	प्रधानमंत्री
3.	आंद्रेज बाबिश	चेक गणराज्य	प्रधानमंत्री
4.	रोड्रिगो पाज	बोलिविया	राष्ट्रपति
5.	कैथरीन कौनौली	आयरलैण्ड	राष्ट्रपति
6.	औहोर ममदानी	USA	न्यूयॉर्क के मेयर
7.	ज्ञानेश कुमार	भारत	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष

युद्धाभ्यास

	युद्धाभ्यास	भागीदार	प्रकार	स्थान	संस्करण
1.	हरिमाऊ शक्ति-2025	भारत-मलेशिया	थल सेना	महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (बीकानेर) (6-18 दिसंबर)	5 वाँ
2.	डेजर्ट साइक्लोन	भारत-UAE	थल सेना	UAE	दूसरा
3.	एकुवैरिन	भारत-मालदीव	थल सेना	केरल	14 वाँ
4.	अभ्यास एकता-2025	भारत-मालदीव	समुद्री अभ्यास	मालदीव	8 वाँ
5.	गरूड़ शक्ति	भारत-इंडोनेशिया	संयुक्त विशेष बल अभ्यास	हिमाचल प्रदेश	10 वाँ
6.	अभ्यास गरूड़-25	भारत-फ्रांस	वायु सेना	फ्रांस	8 वाँ

- **ऑपरेशन सागर बंधु** → इसके तहत भारत ने चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को 1000 टन मानवीय सहायता पहुँचायी।
  चार युद्ध पोत भी तैनात किए- 1. INS घड़ियाल 2. LCU 54 3. LCU 51 4. LCU 57

महत्वपूर्ण तथ्य

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की 34 वीं बैठक (लंदन) में भारत 40 वीं सदस्य परिषद के लिए चुना गया। (सदस्य परिषद की श्रेणी-B में वर्ष 2026-27 के लिए)
- UNESCO के 43 वें आम सम्मेलन (उज्बेकिस्तान) में भारत वर्ष 2025-29 की अवधि के लिए कार्यकारी बोर्ड में पुनः चुना गया।

CERAMIC ACADEMY

भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) देशों के बीच एक व्यापक समझौता है, जो केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं, निवेश, सरकारी खरीद, विवाद निपटान तथा अन्य नियामक पहलुओं को भी सम्मिलित करता है। इसमें पारस्परिक मान्यता समझौते (Mutual Recognition Agreements) भी शामिल होते हैं, जो साझेदार देशों की भिन्न-भिन्न नियामक व्यवस्थाओं को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वे समान (समतुल्य) परिणाम प्राप्त करती हैं।

भारत–ओमान आर्थिक सहभागिता

❖ **वस्तु व्यापार -**

- वित्त वर्ष 2024–25 में ओमान को भारत का निर्यात 4.06 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। अप्रैल–अक्टूबर 2025 के दौरान निर्यात, लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाते हुए, 2.57 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- वित्त वर्ष 2024–25 में ओमान से भारत का आयात 6.55 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल–अक्टूबर 2025 के दौरान आयात 3.91 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

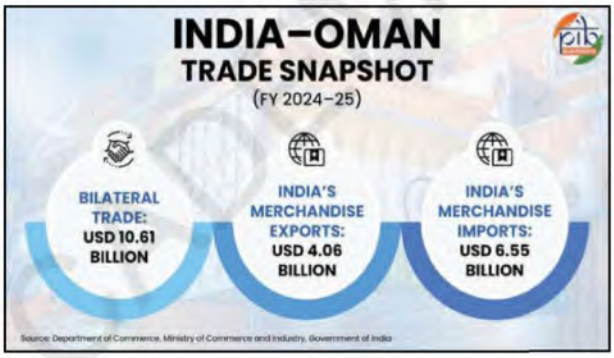

❖ **सेवा व्यापार -**

- भारत से ओमान को सेवाओं का निर्यात 2020 में 397 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 617 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें प्रमुख योगदान दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना सेवाओं, अन्य व्यावसायिक सेवाओं, परिवहन तथा यात्रा सेवाओं का रहा।
- ओमान से सेवाओं का आयात 101 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 159 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें परिवहन, यात्रा, दूरसंचार सेवाएं और अन्य व्यावसायिक सेवाएं प्रमुख क्षेत्र रहे।

महत्वपूर्ण प्रावधान

❖ **वस्तुओं के लिए बाजार तक पहुंच: भारत के लाभ-**

- सीईपीए के अंतर्गत, भारत को ओमान के लिए अपने निर्यात पर 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त बाजार की पहुंच प्राप्त होती है, जो ओमान की 98.08 प्रतिशत शुल्क रेखाओं को कवर करती है और 2022–23 के औसत के आधार पर भारत के व्यापार मूल्य के 99.38 प्रतिशत के बराबर है। सभी शून्य-शुल्क रियायतें समझौते के प्रभाव में आने के पहले दिन से लागू हो जाएंगी, जिससे निर्यातकों को तत्काल ही एक सुनिश्चितता मिल जाएगी।

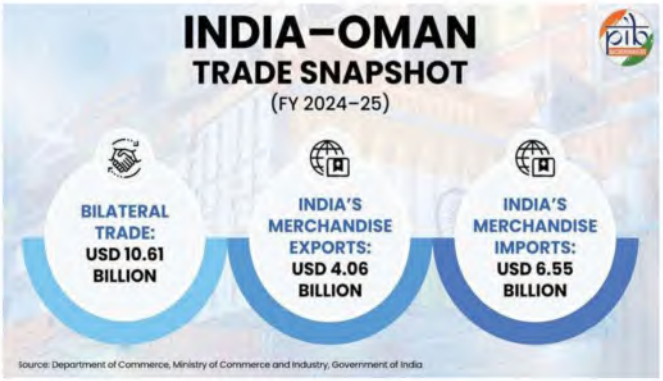

- वर्तमान में, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र व्यवस्था के तहत भारत के निर्यात मूल्य का केवल 15.33 प्रतिशत और शुल्क रेखाओं का 11.34 प्रतिशत (2022–24 के औसत के अनुसार) ही शून्य शुल्क पर ओमानी बाजार में प्रवेश कर पाता है। सीईपीए के साथ, अब बेहतर मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता से ओमान को भारत के उस निर्यात के उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित होने की अपेक्षा है, जिस पर पहले 5 प्रतिशत तक शुल्क लगता था और जिसका मूल्य लगभग 3.64 अरब अमेरिकी डॉलर था।

❖ **भारत का बाजार पहुंच प्रस्ताव और संरक्षण उपाय -**

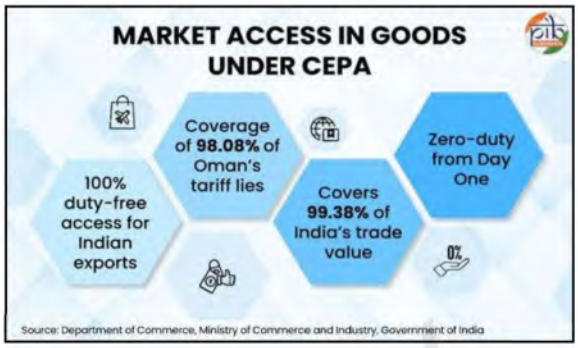

- भारत ने अपनी कुल शुल्क रेखाओं (12,556) में से 77.79 प्रतिशत पर शुल्क उदारीकरण की पेशकश की है, जो मूल्य के आधार पर ओमान से होने वाले भारत के 94.81 प्रतिशत आयात को कवर करता है। साथ ही, भारत ने अनेक शुल्क रेखाओं को अपवाद सूची में रखा है। इस कदम का उद्देश्य प्रमुख घरेलू क्षेत्रों और संवेदनशील मूल्य-श्रृंखला उद्योगों की सुरक्षा करना तथा विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

❖ **भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर मोबिलिटि फ्रेमवर्क** –

- इसमें इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी के लिए कोटा 20% से बढ़ाकर 50% करना शामिल है।कॉन्ट्रैक्ट वाले सर्विस सप्लायर्स के लिए रहने की अनुमति को भी काफी बढ़ा दिया गया है। यह अब 90 दिनों से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है, जिसमें दो साल और बढ़ाने का विकल्प भी है।
- इससे भारतीय कंपनियों को अधिक प्रबंधकीय और विशेषज्ञ कर्मचारी तैनात करने की सुविधा मिलती है।
- किसी भी एफटीए के तहत पहली बार, ओमान ने एक परिभाषित पेशेवर श्रेणी के लिए प्रतिबद्धताएँ भी स्वीकार की हैं, जिनमें लेखा, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, निर्माण और परामर्श सेवाओं में कार्यरत पेशेवर शामिल हैं।

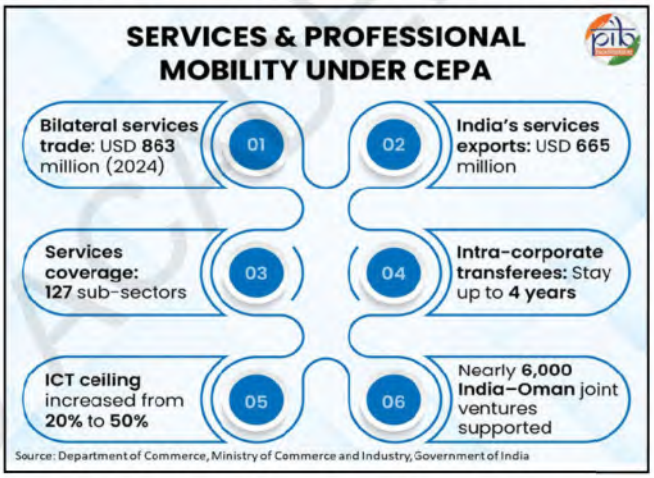

❖ **सेवा उदारीकरण -** सीईपीए के तहत, ओमान ने 127 सेवा उप-क्षेत्रों में व्यापक और गहन बाज़ार पहुँच प्रतिबद्धताएँ स्वीकार की हैं, जो जीएटीएस/सर्वोत्तम एफटीए-प्लस प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें भारत के निर्यात हित वाले प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, जैसे पेशेवर सेवाएँ (कानूनी, लेखा, अभियांत्रिकी, चिकित्सा और संबंधित सेवाएँ), कंप्यूटर और संबंधित सेवाएँ, ऑडियो-विज़ुअल सेवाएँ, व्यावसायिक सेवाएँ और अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा, पर्यावरणीय सेवाएँ, स्वास्थ्य, तथा पर्यटन और यात्रा से संबंधित सेवाएँ।

❖ CEPA भारतीय कंपनियों को ओमान में जरूरी सर्विस सेक्टर में कमर्शियल मौजूदगी के जरिए 100% FDI की भी अनुमति देता है।

राज्य और क्षेत्र-वार निर्यात और रोजगार लाभ

❖ **राज्य-वार प्रमुख कृषि लाभ** –

उत्पाद	राज्य
मांस	उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार
अंडे	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र
मीठे बिस्कुट	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश
मक्खन	गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब
मिठाइयां	कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
आलू, तैयार/संरक्षित	गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र
शहद	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र

CERAMIC ACADEMY

निष्कर्ष

भारत–ओमान सीईपीए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है, जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार, निवेश, पेशेवरों की आवाजाही और नियामक सहयोग शामिल हैं, साथ ही इसमें बाजार की पहुंच और संरक्षण उपायों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण भी बनाए रखा गया है। इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने, रोजगार उत्पन्न होने, आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुदृढ़ होने और भारत एवं ओमान के बीच गहन तथा स्थायी आर्थिक सहभागिता को समर्थन मिलने की अपेक्षा है।

CERAMIC ACADEMY

भारत - न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

भारत और न्यूज़ीलैंड ने मार्च 2025 में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ताओं की घोषणा की थी। कई दौर की बातचीत के बाद 22 दिसंबर 2025 को भारत- न्यूज़ीलैंड एफटीए को अंतिम रूप दिया गया, जिससे यह भारत के सबसे तेज़ी से संपन्न हुए एफटीए समझौतों में से एक बन गया है। इस पर 2026 की पहली छमाही में हस्ताक्षर किये जाएंगे।

द्विपक्षीय व्यापार संबंध

- न्यूज़ीलैंड के साथ भारत की साझेदारी आर्थिक वास्तविकताओं तथा जनता के मजबूत आपसी संबंधों के माध्यम से आकार लेती है। वर्तमान में, न्यूज़ीलैंड ओशिनिया क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- न्यूज़ीलैंड में लगभग 300,000 भारतीय मूल के लोग और एनआरआई रहते हैं, जो उसकी जनसंख्या का लगभग 5% हैं। यह प्रवासी समुदाय सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु का कार्य करता है, जिससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हैं और भारतीय वस्तुओं व सेवाओं की मांग को बढ़ावा मिलता है।
- **व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार :** वर्ष 2023–24 में 873 मिलियन डॉलर से 49% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2024–25 में बढ़कर 1.3 बिलियन डॉलर हो गया।
- **न्यूज़ीलैंड को व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात:** वर्ष 2024–25 में बढ़कर 711 मिलियन डॉलर हो गया, जो 32% का सकारात्मक रुझान दिखाता है।
- **सेवाओं का व्यापार:** न्यूज़ीलैंड को भारत की सेवाओं का निर्यात वर्ष 2024 में 13% बढ़कर 634 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया। प्रमुख क्षेत्र: यात्रा, आईटी और व्यवसाय सेवाएँ
- भारत–न्यूज़ीलैंड व्यापारिक वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2015–16 में 855 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 1,298 मिलियन डॉलर हो गया। इन दस वर्षों में निर्यात में 130% वृद्धि हुई , जबकि आयात केवल 7.21% बढ़ा। वर्ष 2024–25 में न्यूज़ीलैंड से भारत का निर्यात, आयात से अधिक रहा, जिससे दोनों देशों के बीच सकारात्मक व्यापार संतुलन बना।

महत्वपूर्ण प्रावधान

- **निवेश -** न्यूज़ीलैंड दीर्घकालिक आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा।
- **वस्तु व्यापार-**
  - न्यूजीलैंड की बाजार तक पहुँच संबंधी पेशकश में न्यूजीलैंड की 100% टैरिफ लाइनों (8,284 टैरिफ लाइनों) पर शुल्क को तत्काल समाप्त करना (जीरो ड्यूटी) शामिल है।
  - न्यूज़ीलैंड ने प्रमुख भारतीय निर्यातों की लगभग 450 टैरिफ लाइनों में लगभग 10% शुल्क बनाए रखा है, जिनमें वस्त्र/परिधान, चमड़ा और टोपियाँ, सिरामिक्स, कालीन, ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्ज़े शामिल हैं। इसके अलावा, 2025 में 2.2% पर लागू औसत टैरिफ ईआईएफ से शून्य हो जाएगा।

CERAMIC ACADEMY

- भारत ने 70.03% टैरिफ लाइनों में बाजार पहुँच की पेशकश की है, जबकि 29.97% टैरिफ लाइनों को अपवर्जन में रखा है। 30% टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क समाप्ति (ईआईएफ) लागू की गई है, जबकि शेष को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा। कुछ उत्पादों को बाहर रखा गया है जैसे डेयरी (दूध, क्रीम, मट्ठा, दही, चीज़ आदि), पशु उत्पाद (भेड़ के मांस के अलावा), सब्जी उत्पाद (प्याज़, चना, मटर, मक्का, बादाम आदि), चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, सब्ज़ियाँ या माइक्रोबियल फैट और तेल, हथियार और गोला-बारूद, रत्न और आभूषण, तांबा और उससे बने उत्पाद वस्तुएं (कैथोड, कार्ट्रिज, रॉड, बार, कॉइल आदि), एल्युमिनियम और उससे बने उत्पाद (इनगॉट, बिलेट, वायर बार) और दूसरी चीज़ें।
- 30.00% टैरिफ लाइनों पर शुल्क तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा, जिनमें लकड़ी, ऊन, भेड़ का मांस, चमड़ा-कच्ची खालें आदि शामिल हैं।
- 35.60% शुल्क को 3, 5, 7, और 10 साल में चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा, जिनमें पेट्रोलियम तेल, माल्ट एक्सट्रैक्ट, वेजिटेबल ऑयल, और चुनिंदा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, पेप्टोन आदि शामिल हैं।
- 4.37% उत्पादों जैसे वाइन, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, पॉलिमर्स, एल्युमिनियम, आयरन और स्टील और उससे बने उत्पाद आदि पर शुल्क में कमी की गई है।
- 0.06% उत्पाद टैरिफ रेट कोटा के अंतर्गत आते हैं, जिनमें शहद, सेब, कीवी फल, और मिल्क एल्ब्यूमिन सहित एल्ब्यूमिन शामिल हैं।

❖ **सेवाएँ -**

- न्यूजीलैण्ड ने 118 सेवाओं के क्षेत्रों में बाजार पहुँच दी है और 139 उप-क्षेत्रों में एमएफएन (Most Favoured Nation) ट्रीटमेंट दिया है। इसमें आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, टेलीकॉम, निर्माण, पर्यटन और शिक्षा शामिल हैं।
- स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा पर अनुबंध: न्यूज़ीलैंड ने भारत के साथ पहली बार आयुर्वेद, योग और दूसरी पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं में व्यापार को आसान बनाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं ।

❖ **गतिशीलता और शिक्षा -**

- छात्र गतिशीलता : न्यूज़ीलैंड ने किसी भी देश के साथ पहली बार छात्र गतिशीलता और अध्ययन के बाद कार्य करने के वीज़ा से संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है। भविष्य में नीति में बदलाव होने के बावजूद भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान सप्ताह में 20 घंटे तक कार्य कर सकते हैं। अध्ययन के बाद कार्य करने के वीज़ा की अवधि (एसटीईएम स्नातक: 3 वर्ष; मास्टर : अधिकतम 3 वर्ष डॉक्टरेट: अधिकतम 4 वर्ष) होगी।
- पेशेवर मार्ग : कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए भारत के लिए रुचिकर क्षेत्रों में 5,000 वीज़ा का कोटा उपलब्ध है, जिनके लिए अधिकतम 3 वर्षों तक प्रवास किया जा सकता है। इनमें भारत के प्रतिष्ठित पेशे (आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ, संगीत शिक्षक)और अन्य रुचिकर क्षेत्र: आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण शामिल हैं।
- वर्किंग हॉलीडे वीज़ा : हर साल 1,000 युवा भारतीय न्यूज़ीलैंड में 12 महीनों के बहु-प्रवेश का लाभ उठा सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारत की व्यापार कूटनीति के निर्णायक क्षण को दर्शाते हुए समग्र आर्थिक सहयोग के नए अवसरों के द्वार खोलता है। यह समझौता भारतीय वस्तुओं के लिए बाज़ार तक बेहतर पहुँच, सेवाओं और गतिशीलता में अवसरों का विस्तार तथा कृषि, निवेश और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक बनाते हुए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ठोस और व्यापक लाभ प्रदान करता है।

किसानों और एमएसएमई से लेकर छात्रों और कुशल पेशेवरों तक, इस समझौते से व्यापक स्तर पर लाभ होने की उम्मीद है, जो विश्वसनीय और दूरदर्शी वैश्विक साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है और वैश्विक रूप से एकीकृत विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाता है।

CERAMIC ACADEMY

राष्ट्रीय समसामयिकी

भारत की जनगणना 2027 →

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को इसे मंजूरी दी।
- लागत- ₹ 11178.24 करोड़
- आयोजक – गृह मंत्रालय के तहत भारत का रजिस्ट्रार जनरल
- कानूनी आधार – जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियमावली, 1990
- यह देश की कुल 16 वीं एवं स्वतंत्रता के बाद 8 वीं जनगणना होगी।
- भारतीय जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय कार्ययोजना है।
- यह दो चरणों में आयोजित होगी–
  1. घरों की सूची बनाना (Houselisting) एवं आवास (Housing) जनगणना - अप्रैल – सितंबर 2026
  2. जनसंख्या की गणना – फरवरी 2027
     → केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू व कश्मीर तथा राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में सितंबर 2026 में की जायेगी।
- यह देश में डिजिटल माध्यम से पहली जनगणना होगी। इस हेतु निम्नलिखित का उपयोग किया जायेगा – 1. सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) पोर्टल
  2. हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (HLB) क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन
- जनता को स्वयं गणना का विकल्प दिया जायेगा।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल →

- स्थिति – लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
- उद्घाटन – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा
  → 25 दिसंबर 2025 – सुशासन दिवस (अटल बिहारी वाजपेयी की 101 वीं जयंती)
- इसे 65 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया गया है।
- लागत – ₹ 230 करोड़
- इस परिसर में निम्नलिखित की 65 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गयी हैं –
  1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय (मूर्तिकार – राम सुतार)
  2. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
  3. अटल बिहारी वाजपेयी
  } (मूर्तिकार – माटू राम)
- यहाँ 'कमल की आकृति' में एक अत्याधुनिक संग्रहालय (98000 वर्ग फीट) बनाया गया है।

परम वीर दीर्घा →

- उद्घाटन – राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू द्वारा 16 दिसंबर (विजय दिवस) को राष्ट्रपति भवन में।
- इस गैलरी में परम वीर चक्र से सम्मानित सभी 21 विजेताओं के चित्र हैं।
- यह उस गलियारें में बनाई गई है जहाँ पहले ब्रिटिश सहायक अधिकारियों के चित्र लगे थे।

CERAMIC ACADEMY

संथाली भाषा में भारतीय संविधान →

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस पर जारी।
- लिपि- ओल चिकी (1925 ई. में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित)
  - ↳ वर्ष 2025 इसका शताब्दी वर्ष है।
- संथाली भाषा को 92 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से आठवीं अनुसूची में 22 वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय →

- प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर 'सेवातीर्थ' कर दिया गया है।
- साथ ही इसे साउथ ब्लॉक से 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-1' में 'सेवातीर्थ कॉम्पलेक्स' में स्थानांतरित किया जा रहा है।

भारत का पहला 'वाइल्डलाइफ सेफ हाईवे' →

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश के NH-45 (भोपाल- जबलपुर) के
- 11.96 कि.मी. लंबे हिस्से (हिरन- सिंदुर खंड) पर शुरू।
- इसमें 2 कि.मी. लंबे हिस्से पर 'रैबल स्ट्रॉप रैड मार्किंग' की गई है।
- यह दुर्गावती टाईगर रिजर्व (नौरादेही अभयारण्य) से गुजरता है।
- प्रेरणा - शेख जायद रोड (दुबई)

पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना-2025 →

- शुभारंभ- 31 अक्टूबर, 2025 (कोच्चि)
  - ↳ केन्द्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कूरियन द्वारा
- संस्करण- 5 वाँ
- नोडल एजेंसी - ICAR- केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसंधान संस्थान (CMFRI)
- वित्तपोषण- केन्द्रीय मत्स्यपालन विभाग
- परिचालन भागीदार- भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (FSI)
- टैग लाइन / स्लोगन - 'स्मार्ट जनगणना, स्मार्ट मत्स्यपालन'
- अवधि- 3 नवंबर - 18 दिसंबर (45 दिन)
- लक्ष्य- 9 तटीय राज्यों एवं 4 संघ शासित प्रदेशों के 4-5 गाँवों के लगभग 12 लाख से अधिक मछुआरा परिवारों को कवर किया जाएगा।
- CMFRI द्वारा विकसित निम्नलिखित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा-

  1. व्यास-NAV 2. व्यास-भारत 3. व्यास-सूत्र

CERAMIC ACADEMY

सारंडा वन (झारखण्ड)→

- सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड सरकार को सारंडा वन के 31468 हेक्टेयर क्षेत्र को 'वन्यजीव संरक्षण
- अधिनियम, 1972' के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के निर्देश दिए।
- सुप्रीम कोर्ट पीठ – जस्टिस बी. आर गवई एवं विनोद चंद्रन
- सारंडा वन एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक साल वनों में से एक है।
- इसे 'सात सौ पहाड़ियों की भूमि' भी कहा जाता है।

भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत→

- वाणिज्यिक संचालन का शुभारंभ – 11 दिसंबर 2025
  - ↳ केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा वाराणसी के नमो घाट से।
- निर्माण – कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
  - ↳ सहयोग – भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)
- यह 'लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन' (LT-PEM) ईंधन सेल प्रणाली पर आधारित है।
- यह हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर उप-उत्पाद के रूप में पानी उत्सर्जित करता है।
- अतः यह शून्य उत्सर्जन पोत है।

यात्री क्षमता	गति	लंबाई
50 यात्री	6.5 नॉट्स	24 मीटर

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली→

- भारत का पहला 'वाटर पॉजिटिव' एयरपोर्ट बना।
- वाटर पॉजिटिव का अर्थ है – उपयोग किए गए जल से अधिक मात्रा में जल का पुनर्भरण।
- नई दिल्ली में आयोजित 'वाटर इनोवेशन समिट' में यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान→

- प्रारंभ – 4 दिसंबर, 2025 (नई दिल्ली)
- अवधि – 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 (100 दिन)
- क्रियान्वयन – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के सहयोग से –
  1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2. ग्रामीण विकास मंत्रालय 3. शिक्षा मंत्रालय
- यह अभियान तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा।

प्रशासन गाँव की ओर अभियान→

- अवधि – 19 से 25 दिसंबर, 2025
- 'सुशासन सप्ताह 2025' के तहत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा।
- यह 2-31 अक्टूबर तक केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में आयोजित विशेष अभियान 5.0 का विकेन्द्रीकृत संस्करण है।

CERAMIC ACADEMY

विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता (WSAC)–2025

- आयोजन– ताइपे (ताइवान)
- संस्करण– तीसरा
- प्रथम स्थान– संयुक्त अरब अमीरात
- भारत– 8 वाँ स्थान प्राप्त किया। (कुल देश-29)
  - कुल प्रतिभागी– 21
  - भारत ने 21 कौशल श्रेणियों में हिस्सा लिया।
  - यह भारत की पहली भागीदारी थी।
  - पदक– 1 रजत, 2 कांस्य एवं 3 उत्कृष्टता पदक

पदक	श्रेणी	पदक विजेता
रजत	पेंटिंग और डेकोरेटिंग	मुस्कान
कांस्य	इंडस्ट्रिल डिजाइन टेक्नॉलॉजी	
कांस्य	रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन	शिवम सिंह और दिनेश आर
उत्कृष्टता पदक	सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर बिजनस	मोहम्मद मफ़ाज़ पी आर
उत्कृष्टता पदक	वेब टेक्नॉलॉजी	आदित्य नंदन
उत्कृष्टता पदक	इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन	धनुष एम जी

सम्मेलन/कार्यक्रम/महोत्सव

UNESCO अंतर सरकारी समिति का 20 वाँ सत्र

- आयोजन– लाल किला, नई दिल्ली (8–13 दिसंबर)
- भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की।
- अध्यक्षता– विशाल वी. शर्मा (UNESCO में भारत के स्थायी प्रतिनिधी)
- नोडल एजेंसी– संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए UNESCO ने 17 अक्टूबर 2003 को पेरिस में अपने 32 वें आम सम्मेलन के दौरान 2003 कन्वेंशन को अपनाया।
- दिपावली– 10 दिसंबर को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल।
  - ↳ यह भारत की ओर से शामिल 16 वाँ तत्व।

कृष्णवेणी संगीता नीरजनम–2025

- यह कर्नाटक संगीत महोत्सव है।
- आयोजन– विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश)
- विषय– तेलुगु संगीत परंपराओं की समृद्धि का उत्सव
- आयोजक– पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी और आंध्रप्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग
- संस्करण– तीसरा

CERAMIC ACADEMY

EARTH समिट–2025 →

- आयोजन– गांधीनगर (गुजरात) (5-6 दिसंबर)
- उद्घाटन- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा
- संस्करण– दूसरा
- आयोजक – नाबार्ड एवं इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI)
- विषय– वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना।
- अमित शाह ने 'सहकार सारथी' की 13 से अधिक नई सेवाएँ एवं उत्पाद लॉन्च किए–
  1. Digi KCC– किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटल स्वरूप।
  2. ePACS– प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।
  3. सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की पायलट परियोजना।
  4. सहकारी बीमा योजना
  5. विश्व का सबसे बड़ा अनाज भण्डारण एप्लीकेशन
  6. सहकार शासन सूचकांक (CGI)
  7. शिक्षा सारथी
  8. वेबसाइट सारथी
  9. सारथी टेक्नोलॉजी फोरम
  10. कैम्पेन सारथी

WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन →

- आयोजन– नई दिल्ली (17– 19 दिसंबर)
- संस्करण– दूसरा
- आयोजक – विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- विषय– संतुलन की बहाली : स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास
- WHO के महानिदेशक – डॉ. ट्रेडोस अदनोम घेब्रेयेसस
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 19 दिसंबर को निम्नलिखित पहलें लॉन्च की गई–
  1. आयुष मार्क – आयुष उत्पादों की गुणवत्ता के लिए वैश्विक मानक।
  2. मेरा आयुष एकीकृत सेवा पोर्टल (MAISP)
  3. 'अश्वगंधा' पर स्मारक डाक टिकिट जारी किया गया।
  4. नई दिल्ली में WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया।
  5. पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक पुस्तकालय – वैज्ञानिक डेटा और नीति दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव–2025 →

- आयोजन– पंचकूला (हरियाणा) (6-9 दिसंबर)
- विषय– विज्ञान से समृद्धि : आत्मनिर्भर भारत के लिए
- संस्करण– 11वाँ
- नोडल मंत्रालय – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- सहयोगी संस्था– विज्ञान भारती
- समन्वयक संस्थान– भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे
- उद्देश्य– पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ना।
- इसके तहत नई दिल्ली में 'विज्ञानिका– विज्ञान साहित्य महोत्सव' आयोजित किया गया।

CERAMIC ACADEMY

काशी–तमिल समागम 4.0 →

- उद्घाटन समारोह – वाराणसी (2 दिसंबर)
- समापन समारोह – रामेश्वरम (15 दिसंबर)
- विषय– लेट्स लर्न तमिल – तमिल करकलम
- संस्करण– चौथा
- नोडल मंत्रालय – केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय
- प्रमुख कार्यक्रम–
  1. तमिल करकलम – वाराणसी के स्कूलों में तमिल पढाना
  2. तमिल करयोम – काशी क्षेत्र के 300 छात्रों के लिए तमिल सीखने का स्टडी टूर (तमिलनाडु)
  3. ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान– 2 से 10 दिसंबर
     ↳ तेनकासी (तमिलनाडु) से काशी तक।

पेसा (PESA) महोत्सव →

- PESA– अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम, 1996
- आयोजन – विशाखापतनम (आंध्रप्रदेश) (23-24 दिसंबर)
- आयोजक – पंचायती राज मंत्रालय और आंध्रप्रदेश पंचायती राज विभाग
- महोत्सव की शुरुआत R.K. बीच पर 'पेसा रन' से हुई।
- पेसा दिवस (24 दिसंबर) पर निम्नलिखित पहलें लॉन्च की गई–
  1. पेसा पोर्टल 2. पेसा संकेतक 3. जनजातीय भाषाओं में पेसा प्रशिक्षण मॉड्यूल
  4. हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले पर ई-पुस्तक
- खेल प्रतियोगिता–

		पेसा दौड़	तीरंदाजी	कबड्डी
पुरुष वर्ग	प्रथम	अतुल चिंधाड़े (महाराष्ट्र)	कृष्ण पिंगुआ (झारखण्ड)	मध्यप्रदेश
	द्वितीय	सूरज मशी (महाराष्ट्र)	बद्रीलाल मीणा (राजस्थान)	–
महिला वर्ग	प्रथम	राज कुमारी (राजस्थान)	खुशी नानोमा (राजस्थान)	झारखण्ड
	द्वितीय	हीरा सांगा (झारखण्ड)	अनुराधा कुमारी (झारखण्ड)	–

मुख्य सचिवों का 5 वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन →

- आयोजन – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली (26-28 दिसंबर)
- अध्यक्षता – प्रधानमंत्री
- थीम – विकसित भारत के लिए मानव पूँजी।

AI का महाकुंभ →

- आयोजन – नई दिल्ली
- आयोजक – गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
- सहयोग – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं आउटलुक पत्रिका
- थीम– AI विकास – AI का महाकुंभ

CERAMIC ACADEMY

राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन–2025 →

- आयोजन– पंचकुला (हरियाणा) (24 दिसंबर)
- विषय– सहकार से समृद्धि – सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका
- आयोजक – कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको)

	सम्मेलन/कार्यक्रम/महोत्सव	स्थान	अन्य तथ्य
1.	श्रम एवं रोजगार शिखर सम्मेलन	नई दिल्ली	आयोजक – केन्द्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ
2.	आतंकवाद निरोधी सम्मेलन	नई दिल्ली	आयोजक – राष्ट्रीय जाँच एजेंसी
3.	उद्योग संपर्क कार्यक्रम	नई दिल्ली	आयोजक – DRDO
4.	सशक्त समाज, समृद्ध भारत सम्मेलन	नई दिल्ली	
5.	सरस आजीविका फूड फेस्टिवल	नई दिल्ली	
6.	22 वाँ CII वार्षिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन	नई दिल्ली	
7.	अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरिक्षक सम्मेलन	रायपुर (छत्तीसगढ़)	संस्करण– 60 वाँ थीम– विकसित भारत : सुरक्षा आयाम
8.	विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन	देहरादून	थीम– The 5Es for Disaster Resilience
9.	भारत – फ्रांस AI नीति गोलमेज सम्मेलन	IISc बेंगलुरु	संस्करण– तीसरा
10.	पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन	चेन्नई	आयोजक – राष्ट्रीय हरित अधिकरण
11.	10 वाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव –2025	हरियाणा	भागीदार राज्य – मध्यप्रदेश
12.	युवा बिजनेस महासम्मेलन	अहमदाबाद (GJ)	आयोजक – विश्व उमिया फाउंडेशन
13.	लोक सेवा आयोगों का 26 वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन	हैदराबाद (तेलंगाना)	आयोजक – तेलंगाना लोक सेवा आयोग उद्घाटन – राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मु द्वारा

महत्वपूर्ण तथ्य

- केरल– चरम गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना।
- मध्यप्रदेश– ओंकारेश्वर मध्यप्रदेश का 27 वाँ वन्यजीव अभयारण्य।
- ब्रह्मपुत्र नदी– केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी (असम) में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के पहले नदी टर्मिनल का उद्घाटन किया।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने हैदराबाद में नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की।
- गुजरात– रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में टाईगर की स्थायी उपस्थिति दर्ज करने के बाद गुजरात को 33 बाद 'टाईगर स्टेट' का दर्जा प्रदान किया गया है।
- मध्यप्रदेश– हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया।
- गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए अग्निवीरों का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है।

CERAMIC ACADEMY

आर्थिक समसामयिकी

₹ भारत की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना →

- उद्घाटन – 3 दिसंबर 2025 को केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना के निर्माण (स्टील-कटिंग) का वर्चुअली उद्घाटन किया।
- विकास- दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला (गुजरात) के लिए
- निर्माण – आत्रेय शिपयार्ड, गोवा द्वारा
  - ↳ पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के 'ग्रीन टग ट्रांजिशन' प्रोग्राम के तहत
- क्षमता – 60 टन बोलार्ड पूल
- लक्ष्य – वर्ष 2030 तक 50 ग्रीन टग शामिल करना।
  - ↳ प्रथम चरण (2024-27) में 16 टग तैनात किए जाएंगे।
- प्रथम चरण में निम्नलिखित पोर्ट प्राधिकरणों में 2-2 टग तैनात किए जाएंगे –
  1. दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण
  2. पारादीप पोर्ट प्राधिकरण
  3. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण
  4. वी. ओ. चिदंबनार पोर्ट प्राधिकरण

  शेष 8 प्रमुख बंदरगाहों पर एक-एक टग तैनात किया जाएगा।
- उद्देश्य – भारत के समुद्री डीकार्बोनाइजेशन के प्रयासों को तेजी देना।

₹ अमोनिया-यूरिया उर्वरक संयंत्र →

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को नामरूप (असम) में आधारशिला रखी।
- घोषणा – केन्द्रीय बजट 2025-26 में
- लागत – ₹ 10601 करोड़
- विकास- असम बैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (AVFCL)
- यह वर्ष 2030 तक ऑपरेशनल होगा।
- वार्षिक उत्पादन क्षमता – 12.7 लाख टन
- इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया।

₹ तीन नयी एयरलाइंस को मंजूरी →

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय तीन एयरलाइंस को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी किया –
  1. शंख एयरलाइन (उत्तरप्रदेश)
  2. अलहिंद एयरलाइन (केरल)
  3. फ्लाई एक्सप्रेस
- यह वर्ष 2026 से अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू कर सकती हैं।

₹ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस – 24 दिसंबर →

- नए मानकों की घोषणा की गई –

इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर मानक	बम निरोधक प्रणालियों के लिए मानक
IS 19262 : 2025	IS 19445 : 2025

CERAMIC ACADEMY

₹ कोलसेतु विंडो (CoalSETU) →

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 दिसंबर 2025 को कोयला लिंकेज निलामी के लिए इसे मंजूरी दी।
- CoalSETU – Coal Linkage for Seamless, Efficient & Transparent Utilisation
- इसे वर्ष 2016 की 'नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर' (NRS) नीति में एक अलग विंडो के रूप में जोड़ा गया है।
- कोयला लिंकेज धारक अपनी कोयला लिंकेज मात्रा के 50% तक कोयले का निर्यात करने के पात्र होंगे।
- इस विंडो के तहत कोकिंग कोल की निलामी नहीं होगी।

₹ UPI (Unified Payment Interface) →

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की जून 2025 की रिपोर्ट 'ग्रोइंग रीटेल पेमेंट सिस्टम' में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रियल फास्ट-पेमेंट सिस्टम माना गया।
- SI वर्ल्डवाइड की 2024 की रिपोर्ट 'प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम' के अनुसार, UPI की ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में लगभग 49% हिस्सेदारी है।

₹ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान →

- अवधि- 17 सितंबर - 2 अक्टूबर
- यह केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रमुख सहयोगी है।
- तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब जीते –
  1. एक माह में किसी हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण – 32149711
  2. एक सप्ताह में स्तन कैंसर जांच के लिए ऑनलाइन सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण – 9943493
  3. राज्य स्तर पर एक सप्ताह में जीवन संकेतों की जांच के लिए ऑनलाइन सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण – 125406

₹ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का नया लोगो →

- 'वन स्टेट वन आरआरबी' पहल के तहत।
- सभी 28 आरआरबी के लिए एक सिंगल और यूनिफाइड ब्रांड पहचान बनाने हेतु।
- इसकी विशेषताएं हैं –
  - ऊपर की ओर संकेत करता तीर – प्रगति का प्रतीक
  - हाथ – पोषण का प्रतीक
  - लौ – ज्ञानोदय का प्रतीक
  - गहरा नीला रंग – वित्त और भरोसे का प्रतीक
  - हरा रंग – जीवन और विकास का प्रतीक

Note:- 'वन स्टेट वन आरआरबी' पहल की विस्तृत जानकारी (अप्रैल 2025 करेंट अफेयर्स पेज न.- 35)

₹ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर द्वरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए रिलायंस जियो के साथ समझौता किया।

CERAMIC ACADEMY

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAMG) अधिनियम, 2025

18 दिसंबर,2025	19 दिसंबर,2025	21 दिसंबर,2025
लोकसभा से पारित	राज्यसभा से पारित	राष्ट्रपति ने मंजूरी दी

- यह अधिनियम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005' (मनरेगा) को प्रतिस्थापित करेगा।
- यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ संयोजित करता है।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं है-

- **रोजगार की वैधानिक गारंटी [धारा-5(2)] -** यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, बशर्ते परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो।
- **कृषि और ग्रामीण श्रम के बीच संतुलन -** बुवाई और कटाई के चरम सीजन के दौरान कृषि से संबंधित गतिविधियों हेतु कृषि श्रम की उपलब्धता आसान करने के लिए, यह अधिनियम राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की समेकित विराम अवधि अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है। (धारा 6)
  श्रमिकों को मिलने वाले कुल 125 दिनों के रोज़गार के अधिकार यथावत बनी रहेगी, जिसे शेष अवधि में प्रदान किया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादकता और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के मध्य संतुलित समायोजन सुनिश्चित होता है।
- **समय पर मज़दूरी भुगतान -** यह अधिनियम मज़दूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा किसी भी स्थिति में कार्य की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर किए जाने को अनिवार्य करता है (धारा 5(3))।
  निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने की स्थिति में, अनुसूची-II में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विलंब मुआवज़ा देय होगा, जिससे मज़दूरी सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाता है और श्रमिकों को विलंब से संरक्षण प्रदान किया जाता है।
- **टिकाऊ और उपयोगी ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ा रोजगार -** इस अधिनियम के अंतर्गत मज़दूरी रोज़गार को चार प्राथमिक विषयगत क्षेत्रों में टिकाऊ सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है:
  1. जल सुरक्षा एवं जल से संबंधित कार्य
  2. मुख्य ग्रामीण अवसंरचना
  3. आजीविका से संबंधित अवसंरचना
  4. प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्य

  सभी कार्य बॉटम-अप एप्रोच यानि गाँव स्तर से प्रस्तावित किए जाते हैं, तथा सृजित सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाता है, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का कंवर्जेंस, विखंडन से बचाव और स्थानीय ज़रूरत के अनुसार आवश्यक ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण सेचूरेशन लक्ष्य के आधार पर परिणाम-आधारित योजना सुनिश्चित हो सके।
- **राष्ट्रीय स्तर पर अभिसरण के साथ विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण** - सभी कार्य 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं' से प्रारंभ होते हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण प्रकियाओं के माध्यम से तैयार किया जाता है तथा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इन योजनाओं को पीएम गति शक्ति सहित राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ डिजिटल एवं स्थानिक रूप (spatially integrated) से एकीकृत किया जाता है, जिससे संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण के अंतर्गत कन्वर्जेंस संभव होता है, जबकि स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत निर्णय निर्माण को यथावत बनाए रखा जाता है।
  यह एकीकृत योजना निर्माण का फ्रेमवर्क, मंत्रालयों और विभागों को कार्यों की अधिक प्रभावी योजना बनाने और क्रियान्वयन करने में सक्षम बनाएगा, दोहराव से बचाव और सार्वजनिक संसाधनों की अपव्यय रोकने में सहायक होगा, तथा सेचूरेशन-आधारित परिणामों के माध्यम से विकास की गति को तेज़ करेगा।
- **विकेन्द्रीकरण और पंचायतों की भूमिका-** यह अधिनियम योजना बनाने या क्रियान्वयन का केंद्रीकरण नहीं करता है। धाराएँ 16 से 19 तक, पंचायतों, कार्यक्रम अधिकारियों और जिला प्राधिकारियों में, उपयुक्त स्तरों पर योजना, क्रियान्वयन और निगरानी की शक्तियाँ निहित करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केवल दृश्यता, कन्वर्जेंस और समन्वय किया जाएगा, न कि स्थानीय निर्णय लेने के अधिकार लिए जाएंगे।

CERAMIC ACADEMY

❖ **सुधारित वित्तीय संरचना -** यह अधिनियम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जिसे राज्यों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित और क्रियान्वित किया जाएगा। व्यय-साझेदारी का पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, तथा विधानसभारहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण का है।

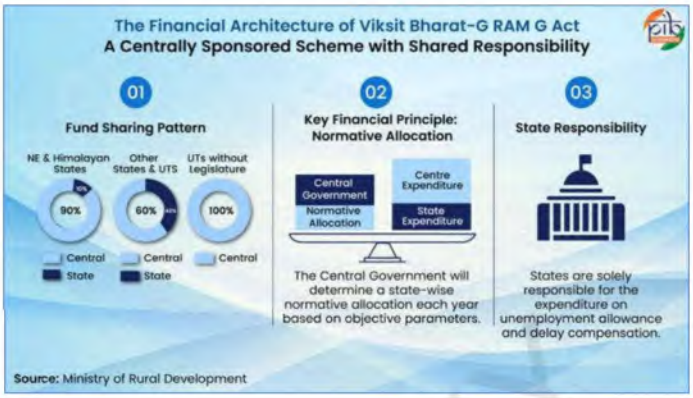

❖ **बेरोजगारी भत्ता -** निर्धारित अवधि में रोजगार न मिलने पर राज्य सरकारें अधिनियम के अनुसार 15 दिनों के पश्चात बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य होंगी।

❖ **मानक आधारित आवंटन -** केंद्र सरकार निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर मानक आवंटन जारी करेगी। मानक आंवटन से अतिरिक्त व्यय की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

❖ **प्रशासनिक क्षमता की सुदृढ़ता -** प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे बेहतर मानव संसाधन उपलब्धता, प्रशिक्षण, तकनीकी क्षमता तथा मैदानी स्तर पर सहायता सुदृढ़ होती है और संस्थानों की परिणामों को प्रभावी रूप से प्रदान करने की क्षमता मज़बूत होती है।

❖ **विशेष छूट -** प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार विशेष छूट प्रदान कर सकेगी।

❖ **मजदूरी दर निर्धारण -** केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी; नई दरें लागू होने तक MGNREGA की वर्तमान दरें प्रभावी रहेंगी।

❖ **राज्य योजनाएँ -** विधेयक लागू होने की तिथि से छह माह के भीतर प्रत्येक राज्य अपनी योजना अधिसूचित करेगा।

❖ **कार्यान्वयन और निगरानी प्राधिकरण -** यह कानून राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर मिशन को समन्वित, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए एक स्पष्ट संस्थागत ढांचा बनाता है।

केन्द्रीय और राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें नीतिगत मार्गदर्शन देती हैं, कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं और जवाबदेही को मजबूत करती हैं।

राष्ट्रीय और राज्य संचालन समितियां रणनीतिक दिशा, तालमेल और निष्पादन समीक्षा का संचालन करती हैं।

पंचायती राज संस्थाएं योजना निर्माण और कार्यान्वयन का नेतृत्व करती हैं, जिसमें ग्राम पंचायतें लागत के हिसाब से कम से कम आधा कार्यान्वयन करती हैं।

जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी योजना निर्माण, अनुपालन, भुगतान और सामाजिक लेखा-परीक्षा का प्रबंधन करते हैं। ग्राम सभाएं सामाजिक लेखा-परीक्षा करने और सभी रिकॉर्ड तक पहुंच के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक मजबूत भूमिका निभाती हैं।

❖ **पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक सुरक्षा -** यह कानून अनुपालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को स्पष्ट प्रवर्तन शक्तियों से लैस करता है। यह केंद्र को कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों की जांच करने, गंभीर अनियमितताओं का पता चलने वाली निधि जारी करने को निलंबित करने और कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक या उपचारात्मक उपायों को निर्देशित करने के लिए अधिकृत करता है। ये प्रावधान पूरे सिस्टम में जवाबदेही को मजबूत करते हैं, वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हैं और दुरुपयोग को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाते हैं।

CERAMIC ACADEMY

कानून कार्यान्वयन के हर चरण को कवर करते हुए एक व्यापक पारदर्शिता का ढांचा भी स्थापित करता है। यह अनियमितताओं की शीघ्र पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के इस्तेमाल को सक्षम बनाता है, जो निरंतर मार्गदर्शन और समन्वय प्रदान करने वाली केंद्रीय और राज्य संचालन समितियों द्वारा समर्थित है। चार स्पष्ट रूप से परिभाषित ग्रामीण विकास कार्यक्षेत्रों के माध्यम से एक केंद्रित दृष्टिकोण इनके परिणामों की बारीकी से ट्रैकिंग की अनुमति देता है। पंचायतों को पर्यवेक्षण में एक बढ़ी हुई भूमिका सौंपी गई है, जिसमें तत्क्षण कार्यों की जीपीएस और मोबाइल-आधारित निगरानी शामिल है। तत्क्षण एमआईएस डैशबोर्ड और साप्ताहिक सार्वजनिक घोषणा सार्वजनिक दृश्यता सुनिश्चित करते हैं, जबकि हर छह महीने में कम से कम एक बार अनिवार्य सामाजिक लेखा-परीक्षा सामुदायिक भागीदारी और विश्वास को मजबूत करते हैं।

मनरेगा,2005 बनाम वीबी-जी राम जी अधिनियम,2025

मनरेगा,2005	वीबी-जी राम जी अधिनियम,2025
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी।	प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी।
कार्यों की अनेक और बिखरी हुई श्रेणियाँ, जिनमें रणनीतिक फोकस सीमित है।	जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, जीविका और जलवायु लचीलापन पर केंद्रित 4 स्पष्ट रूप से परिभाषित प्राथमिकता क्षेत्र।
अकुशल मजदूरी की लागत केंद्र सरकार वह करती है, बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारें देती हैं।	मजदूरी के लिए राज्य सहभागिता, अधिकांश राज्यों के लिए 60:40, विशेष श्रेणी क्षेत्रों के लिए 90:10
कोई स्पष्ट वैधानिक "रोक (pause) अवधि" का प्रावधान नहीं।	राज्य वित्तीय वर्ष में 60 दिनों तक कार्य न कराने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
माँग आधारित फंडिंग, जिनमें आवंटन अप्रत्याशित रहते हैं।	मानक फंडिंग जो रोजगार गारंटी की रक्षा करते हुए अनुमानित बजटीकरण सुनिश्चित करती है
योजना निर्माण में ग्राम पंचायत की केंद्रीय भूमिका हैं।	संस्थागत एकीकरण और अवसंरचना योजना को समाहित करती है।

वीबी-जी राम जी अधिनियम,2025 के लाभ

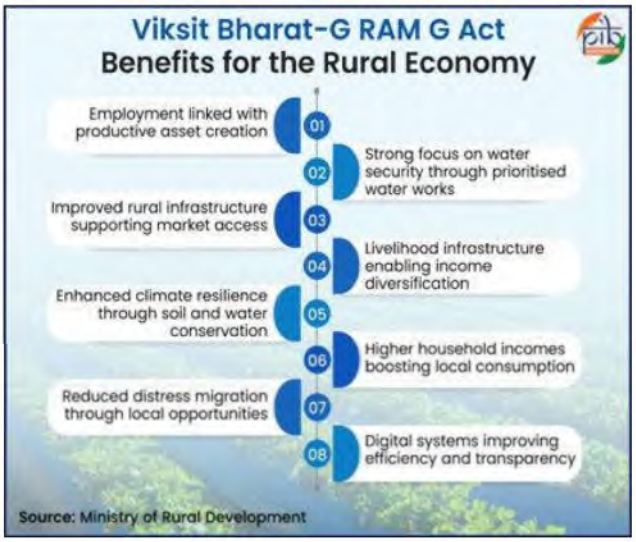

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था -** यह कानून रोजगार सृजन को उत्पादक परिसंपत्ति सृजन से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, जिससे घरेलू आय में वृद्धि होती है और अनुकूलन क्षमता में सुधार होता है। पानी से जुड़े कामों, कृषि और भूजल स्तर में सुधार को प्राथमिकता दी जाती है। सड़क और कनेक्टिविटी जैसे मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश से बाजार तक पहुंच में आसानी होती है, जबकि भंडारण, बाजार और उत्पादन परिसंपत्तियों सहित आजीविका बुनियादी ढांचा आय विविधीकरण को सक्षम बनाता है। जल संचयन, बाढ़ जल निकासी और मृदा संरक्षण पर केंद्रित कार्यों के माध्यम से जलवायु अनुकूलता मजबूत होती है। 125 दिनों के रोजगार की गारंटी घरेलू आय को बढ़ाती है, ग्राम-स्तर की खपत को प्रोत्साहित करती है, और डिजिटल उपस्थिति, मजदूरी भुगतान और डेटा-संचालित योजना के माध्यम से प्रवासन को कम करने में मदद करती है।

CERAMIC ACADEMY

- **किसान -** किसानों को बुवाई और कटाई के मौसम के दौरान सार्वजनिक कार्यों में राज्य-अधिसूचित ठहराव, मजदूरी मुद्रास्फीति की रोकथाम और बेहतर सिंचाई, भंडारण और कनेक्टिविटी की वजह से सुनिश्चित श्रम उपलब्धता से लाभ होता है।

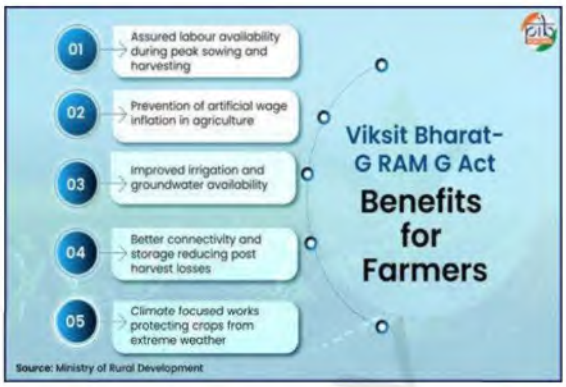

- **श्रमिक -** श्रमिकों को उच्च संभावित कमाई, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अनुमानित काम, सुरक्षित डिजिटल मजदूरी भुगतान और उन परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष लाभ होता है जिन्हें सृजित करने में वे मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्हें एक अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। जब श्रमिकों को काम प्रदान नहीं किया जाता है तो उन्हें दैनिक बेरोजगारी भत्ता 15 दिनों के बाद मिल जाता है। इसकी जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। मजदूरी की दरों और शर्तों को नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाना है, जो यह सुनिश्चित करे कि इसमें लचीलापन हो और साथ ही श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा तथा रोजगार के समयबद्ध प्रावधान को बढ़ावा मिले।

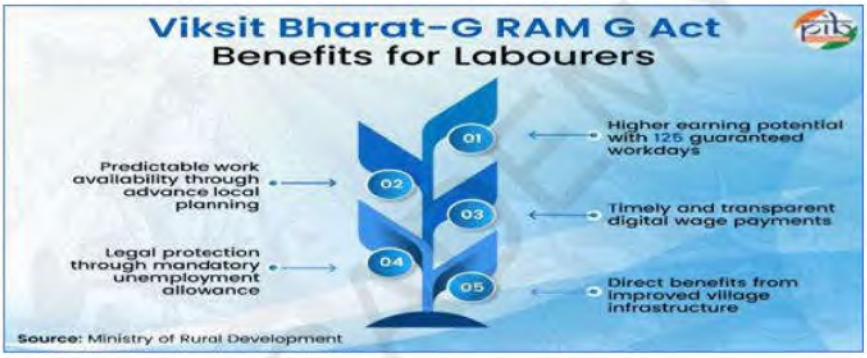

निष्कर्ष

विकसित भारत- रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025, भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक निर्णायक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मनरेगा ने समय के साथ भागीदारी, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण लाभ हासिल किया, जबकि लगातार संरचनात्मक कमजोरियों ने इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। नया कानून एक आधुनिक, जवाबदेह और अवसंरचना-केंद्रित ढांचे के माध्यम से उनकी कमियों को दूर करते हुए पिछले सुधारों पर आधारित है।

गारंटीकृत रोजगार का विस्तार करके, राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और कार्यों के बीच ताल-मेल बिठाते हुए मजबूत डिजिटल शासन को शामिल करके, यह कानून ग्रामीण रोजगार को सतत विकास और यथोचित आजीविका के लिए एक कार्यनीतिक साधन के रूप में स्थापित करता है, जो पूरी तरह से विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जुड़ा हुआ है।

CERAMIC ACADEMY

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी

इसरो द्वारा CE 20 क्रायोजैनिक इंजन का सफल परीक्षण→

- इसरो ने 7 नवंबर को इसरो प्रपल्शन कॉम्पलेक्स (IPRC), महेंद्रगिरी में CE 20 क्रायोजैनिक इंजन पर 'बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट टैस्ट' का सफल परीक्षण किया।
- इससे बिना किसी बाह्य ईंधन की सहायता के इंजन का स्थिर संचालन संभव होगा।
- यह परीक्षण निर्वात में 10 सैकण्ड की अवधि के लिए किया गया।
- इसरो ने संभवत: विश्व में पहली बार बिना किसी सहायक थ्रस्ट सिस्टम के गैस-जनरेटर
- साइकिल क्रायोजैनिक इंजन का बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- लाभ- इंजन की री-स्टार्ट क्षमता बढ़ेगी, प्रक्षेपण यान की पैलोड क्षमता बढ़ेगी।

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 संचार उपग्रह→

- इसरो द्वारा LVM-3 M-6 रॉकेट से 24 दिसंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
- यह प्रक्षेपण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और अमेरिका की AST स्पेसमोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत किया गया है।
- इस उपग्रह को निम्न भू-कक्षा (LEO) में स्थापित किया गया है।
- यह भारत से प्रक्षेपित किया गया (इसरो द्वारा) अब तक का सबसे भारी (6100 कि.ग्रा.) उपग्रह है।
- यह उपग्रह सर्माटफोन को सीधे हाई-स्पीड सैल्यूलर ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी प्रदान करता है।
- यह वैश्विक LEO तारामंडल (Constellation) का हिस्सा है।

ह्यूमन-रेटेड एल 110 स्टेज विकास इंजन→

- गौदरेज एयरोस्पेस द्वारा इस इंजन को इसरो को सौंपा।
- इस इंजन का उपयोग LVM-3 प्रक्षेपण यान के एल 110 चरण में किया जाएगा।
- LVM-3 प्रक्षेपण यान गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण है।

अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन (ACE-N)→

- इसरो के प्रमुख वी. नारायणन ने तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन (27 नवंबर, 2025) किया।
- स्थापना - अनंत टैक्नोलॉजीज द्वारा।
- उद्देश्य- यह भारत के नैविगेशन सिस्टम नाविक (NavIC) आधारित चिप्स, रिसीवर और अन्य नैविगेशन उपकरणों का विकास करेगा।
- यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का नैविगेशन इनोवेशन हब है।

- इसरो ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज (उत्तरप्रदेश) में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया।

CERAMIC ACADEMY

⚛ अलकनंदा गैलेक्सी →

- NCRA-TIFR, पुणे के शोधकर्त्ताओं- राशि जैन (भरतपुर) एवं योगेश वाडेकर खोजी द्वारा गई।
- NCRA-TIFR :- National Centre for Radio Astrophysics - Tata Institute of Fundamental Research
- खोज के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग किया गया।

रक्षा प्रौद्योगिकी

	आकाश - NG मिसाइल	K-4 बैलेस्टिक मिसाइल
परीक्षण	DRDO द्वारा चांदीपुर टेस्ट रेंज (ओडिशा) में 23 दिसंबर 2025 को।	DRDO द्वारा विशाखापत्तनम तट पर INS अरिघात पनडुब्बी से 23 दिसंबर को।
विकास	DRDO एवं भारत डायनामिक्स लिमिटेड	DRDO
मारक क्षमता	70-80 कि.मी. (गति- 2.5 मैक से अधिक) एक साथ 10-30 लक्ष्यों का मुकाबला	3500 कि.मी.
तकनीकें	यह स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और सॉलिड रॉकेट मोटर से युक्त है।	इसे 'कोल्ड लॉन्च तकनीक' से दागा जाता है। दो चरणीय ठोस ईंधन प्रणाली से युक्त है।

⚛ शेर एके -203 राइफल →

- भारतीय सेना द्वारा पश्चिमी सीमा (राजस्थान बॉर्डर) पर सफल परीक्षण।
- पुरानी इंसास राइफलों को प्रतिस्थापित करेगी।
- निर्माण- इंडो- रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, अमेठी (उत्तरप्रदेश) द्वारा
- परास- 800 मीटर
- क्षमता- 700 राउंड प्रति मिनट

⚛ पायलट एस्केप सिस्टम →

- DRDO द्वारा 2 दिसंबर 2025 को लड़ाकू विमानों हेतु पायलट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण।
- परीक्षण स्थल- टर्मिनल बैलेस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री (TBRL) चण्डीगढ़।
- यह परीक्षण 800 कि.मी. प्रति घण्टा की नियंत्रित गति पर किया गया।
- सहयोग- एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) तथा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)

⚛ WhAP 8x8 →

- Wheeled Armoured Amphibious platform
- हाल में टाटा ने मोरक्को को इसकी पहली खेप की आपूर्ति की है।
- डिजाइन- DRDO एवं टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL)
- यह भारत का पहला एम्फीबियस इन्फैन्ट्री कॉम्बैट व्हीकल है।
- यह सभी प्रकार के इलाकों में संचालन योग्य है।
- इसमें इंटीग्रेटेड पावर पैक के साथ ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन एवं तैरने की क्षमता है।

CERAMIC ACADEMY

⚛ प्रलय मिसाइल →

- DRDO द्वारा 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा तट के पास दो प्रलय मिसाइलों का परीक्षण किया गया।
- प्रलय ठोस प्रणोदक अर्द्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है।
- यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।
- विकास - अनुसंधान केन्द्र इमारत (RCI), हैदराबाद
- गति - 1-1.6 मैक
- परास - 150-500 कि.मी.
- उत्पादन - भारत डायनामिक्स लिमिटेड एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

⚛ पिनाका →

- DRDO ने चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज (ओडिशा) में 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट (LRGR 120) का सफल परीक्षण किया।
- LRGR ने 'टेक्स्टबुक प्रिसिजन' के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया।
- परास - 120 कि.मी.
- डिजाइन - आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा
  - ↳ सहयोग - 1. हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेट्री
    2. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेट्री
    3. रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), हैदराबाद
- LRGR को पिनाका लॉन्चर से लॉन्च किया गया।

⚛ DRDO ने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत विकसित 7 प्रौद्योगिकियाँ सशस्त्र बलों को सौंपी →

1. एयरबोर्न सेल्फ-प्रोटेक्शन जैमर्स के लिए स्वदेशी उच्च वोल्टेज विद्युत आपूर्ति
2. नौसेना जेटी के लिए ज्वार कुशल गैंगवे
3. उन्नत अति निम्न आवृत्ति - उच्च आवृत्ति स्विचिंग मैट्रिक्स प्रणालियाँ।
4. पानी के नीचे प्लेटफॉर्मों के लिए VLF लूप एरियल
5. तीव्र अवरोधक शिल्प के लिए स्वदेशी वॉटरजेट प्रणोदन प्रणाली
6. प्रयुक्त लिथियम आयन बैटरियों से लिथियम प्रीकर्सर की पुनर्प्राप्ती की नई प्रक्रिया
7. दीर्घकालीन पानी के भीतर संवेदन एवं निगरानी अनुप्रयोगों के लिए दीर्घ-जीवन समुद्री बैटरी प्रणाली।

⚛ इंद्रजाल रेंजर →

- भारत का पहला मोबाइल AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोलिंग व्हीकल
- विकास - इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस (हैदराबाद)
- परास → 10 कि.मी. दूर से ड्रोन ट्रैक कर सकता है।
  - ↳ 4 कि.मी. की दूरी तक ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकता है।

⚛ प्रावैग वीर - प्रावैग डायनेमिक्स (बेंगलुरु) द्वारा विकसित देश का पहला इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल।

CERAMIC ACADEMY

हंसा-3 NG →

- यह भारत का पहला पूरी तरह से कंपोजिट एयरफ्रेम वाला दो सीटर प्रशिक्षण विमान है।
- उद्घाटन– केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा 29 नवंबर को बेंगलरू में।
- डिजाइन एवं विकास– वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR) के तत्वाधान में राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (NAL)
- उत्पादन– पायनियर क्लीन एम्प्स
- कुप्पम (आंध्रप्रदेश) में ₹ 150 करोड़ की लागत से एक संयंत्र बनाया जा रहा है जहाँ प्रत्येक वर्ष 100 विमान तैयार होंगे।

इंजन	उड़ान सीमा	उड़ान दक्षता (Endurance)
रोटेक्स 912 iSC-3 स्पोर्ट्स इंजन	620 नॉटिकल मील	7 घण्टे

- इस अवसर पर →
  - सारस MK-2 विमान →
    - # यह स्वदेशी 19 सीटर शॉर्ट हॉल पैसेंजर विमान है।
    - # डिजाइन एवं विकास– वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR) के तत्वाधान में राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (NAL)
    - # यह सैन्य एवं असैन्य दोनों तरह से इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है।
    - # केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 29 नवंबर को बेंगलुरू में इस विमान के लिए बनी 'आयरन बर्ड' सुविधा का उद्घाटन किया।
  - अधिकतम ऊँचाई वाले स्थानों (HAP) के लिए विनिर्माण सुविधा →
    - # उद्घाटन–केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा 29 नवंबर को बेंगलरू में।
    - # भारत की यह पहल लंबी अवधि के मिशनों के लिए 20 कि.मी. से अधिक ऊँचाई पर उड़ान भरने में सक्षम सौर ऊर्जा चालित मानव रहित विमान विकसित करने वाले
    - # देशों की चुनिंदा लीग में शामिल होने की है।
      - ↳ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड एवं जापान।
    - # लक्ष्य–वर्ष 2027 तक पहली पूर्ण उड़ान।
    - # यह निगरानी, दूरसंचार और पर्यावरणीय निगरानी के लिए उपग्रहों का एक लागत प्रभावी विकल्प है।
  - डॉ. जितेन्द्र सिंह ने HAL हवाई अड्डे पर नवीमेट प्रणाली का भी उद्घाटन किया।
  - स्वदेशी 150 किलोग्राम श्रेणी के लोइटरिंग म्यूनिशन UAV के विकास हेतु मैसर्स डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड के साथ CSIR-NAL के सहयोग को औपचारिक रूप दिया।
    - # इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं–

इंजन	परास	Endurance	नेविगेशन	AI सक्षम लक्ष्य पहचान
वांकेल इंजन	900 कि.मी.	6-9 घण्टे	GPS निरीक्षित	

CERAMIC ACADEMY

INS तारागिरी	ASW SWC अंजदीप	INS सिंधुघोष
• नीलगिरी श्रेणी (प्रोजेक्ट 17A) का चौथा फ्रीगेट जहाज। • 28 नवंबर को मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। • निर्माण- मझगांव डॉक शिपबिल्डिंग लिमिटेड • डिजाइन- युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो • यह पूर्व लिएंडर श्रेणी के INS तारागिरी का पुनर्जन्म है। • इसमें संयुक्त डीजल या गैस संयंत्र लगे हैं।	• 8 पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज (ASW SWC) में तीसरा। • 22 दिसंबर को चेन्नई में भारतीय नौसेना में शामिल। • निर्माण- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) • नामकरण- कर्नाटक के कारवार तट पर स्थित अंजदीप द्वीप पर। • भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वाटरजेट युद्धपोत है। • लंबाई- 77 मीटर	• भारतीय नौसेना की पनडुब्बी 19 दिसंबर को मुंबई में सेवामुक्त। • यह सिंधुघोष श्रेणी की पहली पनडुब्बी है। • निर्माण- रूस (किलो क्लास सबमरीन) • इसे अप्रैल 1986 में कमीशन किया गया था।

DSC A20	INAS 335	गश्ती पोत 'अमूल्य'
• गोताखोरी में सहायक स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित पहला जहाज। • 16 दिसंबर को कोच्चि में भारतीय नौसेना में शामिल। • निर्माण- टीटागढ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, कोलकाता • 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC) में पहला जहाज। • यह कैटामारन आधारित पतवार विन्यास वाला जहाज है।	• दूसरा MH60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। • 17 दिसंबर को गोवा स्थित INS हंसा में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन। • अन्य नाम- द ऑस्प्रे	• अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र गश्ती पोतों में तीसरा। 19 दिसंबर को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल। • निर्माण- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। • लंबाई- 51 मीटर • इसके 60% से अधिक घटक स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। • तैनाती- पारादीप (ओडिशा) • गति- 27 समुद्री मील • परिचालन क्षमता- 1500 समुद्री मील

'विजय दिवस एट होम' समारोह →

- आयोजन- आर्मी हाऊस, नई दिल्ली (15 दिसंबर 2025)
  - ↳ वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में।
- भारतीय सेना ने निम्नलिखित स्वदेशी तकनिकों एवं नवाचारों का प्रदर्शन किया-
- Ekam AI →
  - ◆ पूरी तरह से स्वदेशी एवं सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म है।
  - ◆ विकास- न्यूलिक्स (बेंगलुरू) द्वारा
    - ↳ रक्षा मंत्रालय की पहल IDEX-ADITI 2.0 पहल के तहत
  - ◆ यह विदेशी सॉफ्टवेयर या बाहरी क्लाउड प्रणालियों पर निर्भर हुए बिना सूचना के विश्लेषण, दस्तावेज प्रबंधन और निर्णय निर्माण में प्रभावी सहायता प्रदान करता है।

CERAMIC ACADEMY

- **प्रोजेक्ट संभव (SAMBHAV)→**
  - यह एक पोर्टेबल संचार प्रणाली है, जो उपग्रह आधारित मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम है।
  - इस प्रणाली को दूरस्थ, दुर्गम अथवा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्रता से तैनात किया जा सकता है।
  - यह प्रणाली सैनिकों के साथ-साथ नागरिकों के लिए भी विश्वसनीय एवं सुदृढ़ संचार सुनिश्चित करता है।
- **दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पोर्टेबल AI सिस्टम (AI इन ए बॉक्स)→**
  - यह इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी के अभाव वाले क्षेत्रों में सूचना के विश्लेषण, अभियानों की योजना बनाने और निर्णय निर्माण में त्वरित सहायता प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है।
- बेहतर जमीनी जागरूकता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपग्रह चित्र विश्लेषण प्रणाली, जो उपग्रह चित्रों की त्वरित, सटीक और प्रभावी व्याख्या में सक्षम है।
- Silent Electric Tectical Vehicle, स्वदेशी ड्रोन विश्लेषण उपकरण, दुर्गम क्षेत्रों के लिए स्वदेशी ऑल टेरेन वाहन, पुनचक्रित प्लास्टिक से बने पर्यावरण अनुकूल ट्रैक वे आदि का प्रदर्शन किया गया।

❀ सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने टेकनपुर (पंजाब) में पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई 'दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन' का शुभारंभ किया।

❀ **रक्षा समझौते→**

- हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 113 'F-404GnE-IN20' इंजनों की आपूर्ति हेतु लगभग $1 बिलियन का समझौता किया।
  ये इंजन 'LCA तेजस MK-1A' लड़ाकू विमानों में लगाए जाएंगे।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) ने रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सहायता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 22 दिसंबर को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) ने 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत फ्रांस की 'सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ दो सक्षम युद्ध प्रणालियाँ विकसित करने हेतु समझौता किया-
  1. सिग्मा 30 एन डिजिटल रिंग लेजर आइरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम
  2. CM3-MR डायरेक्ट फायरिंग साइट

CERAMIC ACADEMY

अन्य प्रौद्योगिकियाँ

DHRUV64 →

- भारत का पहला स्वदेशी 1.0GHz,64-बिट ड्यूल कोर माइक्रोप्रोसेसर
- इसे डिजिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) कार्यक्रम के तहत डिजाइन किया गया है।
- विकास- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम (MDP) के तहत विकसित तीसरी चिप।
  - ◆ अन्य दो चिप- 1. THEJAS 32 – मलेशिया स्थित सिलटेरा सुविधा केन्द्र में निर्मित।
    2. THEJAS 64 – सेमी कंडक्टर लैब, मोहाली में निर्मित।
  - ◆ DHANUSH 64 एवं DHANUSH 64+ प्रोसेसर विकास के चरण में हैं।

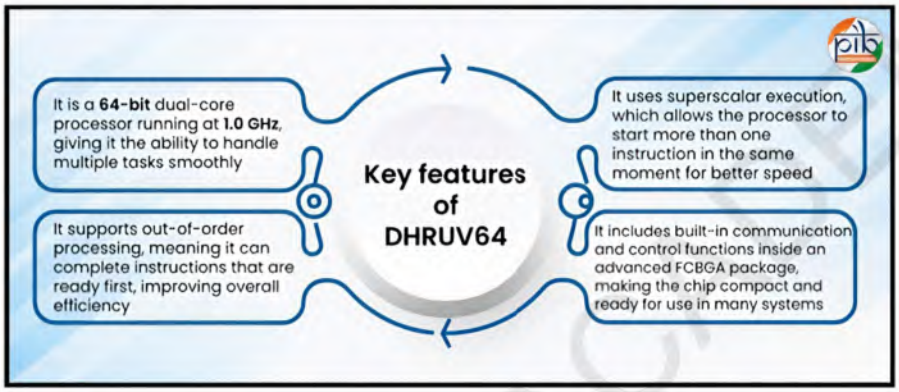

GlowCas9 →

- डॉ. बसुदेव माजी के नेतृत्व में कोलकाता स्थित बोस संस्थान के वैज्ञानिकों ने GlowCas9 नामक CRISPR प्रोटीन बनाया है।
- यह जीन संपादन की प्रक्रिया के समय चमकता है। अतः यह इसे ट्रैक करने को सक्षम बनाता है।
- यह अध्ययन 'एंजवेन्टे केमी इंटरनेशनल एडिशन' में प्रकाशित हुआ है।

दृष्टि (DRISHTI) →

- AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली
- भारतीय रेलवे ने इस हेतु IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया।

ऑन्कोमार्क →

- यह एक AI आधारित फ्रेमवर्क है, जो आण्विक स्तर पर कैंसर के व्यवहार को समझने और निदान करने में मदद करता है।
- विकास- एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोका यूनिवर्सिटी

CERAMIC ACADEMY

पुरस्कार एवं सम्मान

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-2025→

- आयोजन- पणजी (गोवा) (20-28 नवंबर 2025)
- संस्करण- 56 वाँ
- आयोजक- नैशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

फोकस देश	भागीदार देश	स्पॉटलाइट देश
जापान	स्पेन	ऑस्ट्रेलिया

- विशेष सम्मान→
  - उद्घाटन समारोह में- नंदमूरी बालकृष्ण
  - समापन समारोह में- रजनीकांत

पुरस्कार	विजेता
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म (गोल्डन पीकॉक)	स्किन ऑफ यूथ (वियतनाम)
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (रजत मयूर)	संतोष दावखर (मराठी फिल्म-गोंधळ)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (रजत मयूर)	उबेइमार रियोस (फिल्म- ए पोस्ट)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (रजत मयूर)	जारा सोफिया ओस्ताना (फिल्म- लिटिल ट्रबल गर्ल्स)
विशेष ज्यूरी पुरस्कार	अकिनोला डेविस जूनियर (फिल्म-माई फादर्स शैडो)
ICFT यूनेस्को गांधी पदक	एरिक स्वेन्सन (फिल्म-सेफ हाऊस)
सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज (OTT)	बंदिश बैंडिट्स सीजन-2

राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार-2025→

- 3 दिसंबर 2025 को 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किए।
- संबंधित मंत्रालय- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- दो श्रेणियों में कुल 32 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया-
  1. व्यक्तिगत उत्कृष्टता (6 उप-श्रेणियां) 2. संस्थागत श्रेणी (6 उप-श्रेणियां)
- दीपाली शर्मा- जयपुर (राजस्थान)- श्रवणबाधित चित्रकार
  - व्यक्तिगत उत्कृष्टता श्रेणी की 'श्रेष्ठ दिव्यांगजन' उप-श्रेणी में सम्मानित।
  - वर्ष 2024 में 'राजस्थान ललित कला अकादमी राज्य कला पुरस्कार से सम्मानित।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2025→

- 26 दिसंबर 2025 को 'वीर बाल दिवस' के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किए।
- संबंधित मंत्रालय- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- 18 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के 20 बच्चों को सम्मानित किया गया।
  ↳ इनमें राजस्थान से कोई नहीं हैं।

CERAMIC ACADEMY

शिल्प गुरू एवं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार-2023 एवं 2024

- 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मु ने ये पुरस्कार प्रदान किए।
- यह समारोह केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह (8-14 दिसंबर) के तहत किया गया।
- कुल 48 पुरस्कार प्रदान किए गए-
  - 12 शिल्प गुरू पुरस्कार
  - 36 राष्ट्रीय पुरस्कार (इनमें 2 डिजाइनर एवं नवाचार पुरस्कार शामिल हैं)
  - पुरस्कार विजेताओं में 20 महिला कारीगर शामिल हैं।
- राजस्थान के पुरस्कार विजेता-

	शिल्प गुरू पुरस्कार	राष्ट्रीय पुरस्कार		डिजाइनर एवं नवाचार पुरस्कार
विशेषता	हस्तशिल्प के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान	उत्कृष्ट शिल्प कौशल हेतु प्रदान किया जाता है।		हस्तशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोगों हेतु।
राशि	₹ 3.50 लाख	₹ 2 लाख		₹ 3 लाख
विजेता	वर्ष 2024 के लिए कमलेश शर्मा (लकड़ी पर बारीक नक्काशी एवं तारकशी)	वर्ष 2024	वर्ष 2023	वर्ष 2023 के लिए धापा देवी एवं कविता चौधरी (क्रमशः जयपुर रग्स की शिल्पकार एवं डिजाइनर)
		1. मोती लालवानी (धातु शिल्प) 2. गायत्री रानी (मीनाकारी) 3. अनिल प्रजापत (टेराकोटा)	1. रौशन धीपा (हैण्ड ब्लॉक प्रिंट) 2. पवन कुमावत (अेमस्टोन कर्विंग)	

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2025

- 14 दिसंबर 2025 को 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मु ने ये पुरस्कार प्रदान किए।
- ये पुरस्कार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की एक पहल हैं।
- ये पुरस्कार 7 व्यापक श्रेणियों के 28 सैक्टरों में प्रदान किए गए।
- इस वर्ष 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं कंटेंट क्रिएटर्स' के लिए नई श्रेणी शामिल की गई।
- इस वर्ष के पुरस्कारों में 26 प्रथम पुरस्कार, 5 द्वितीय पुरस्कार, 26 मेरिट प्रमाण-पत्र और नवाचार पुरस्कारों के लिए 3 मान्यता प्रमाण-पत्र शामिल हैं।
- संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत राज्य प्रदर्शन पुरस्कार-

समूह	समूह-1	समूह-2	समूह-3	समूह-4	समूह-5
प्रथम पुरस्कार	कर्नाटक	आंध्रप्रदेश	केरल	असम	चण्डीगढ़

- इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर को इमारत श्रेणी के कॉलेज/यूनिवर्सिटी क्षेत्र में मेरिट प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।
- 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं कंटेंट क्रिएटर्स' के विजेता-

  1. मुस्कान (हरियाणा) 2. वंशिका पांडे (मध्यप्रदेश) 3. वैदिका खत्री (नई दिल्ली)

CERAMIC ACADEMY

ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता-2025 →

- 14 दिसंबर 2025 को 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु ने इसके विजेताओं को सम्मानित किया।
- यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की एक पहल है।

	समूह-A (कक्षा-5,6 एवं 7)	समूह-B (कक्षा-8,9 एवं 10)
प्रथम पुरस्कार (₹ 1 लाख)	अनुज प्रिंस	सौम्यजीत मलिक
द्वितीय पुरस्कार (₹ 50 हजार)	अर्पिता मंडल	स्टैनजिन चोस्यांग्स
तृतीय पुरस्कार (₹ 30 हजार)	खुशबू यादव	युवराज सिंह ऑली

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार-2025 →

- 23 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु ने ये पुरस्कार प्रदान किए।
- भारत सरकार द्वारा चार श्रेणियों एवं 13 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है।
- इस वर्ष 24 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किया गया-

विज्ञान रत्न	विज्ञान श्री	विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर	विज्ञान टीम
आजीवन उपलब्धियों हेतु	किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान हेतु।	45 वर्ष तक के युवा वैज्ञानिकों को असाधारण योगदान हेतु।	3 या अधिक वैज्ञानिकों की टीम को
विजेता-प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर (मरणोपरांत)	8 वैज्ञानिक	14 वैज्ञानिक	अरोमा मिशन CSIR

चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड-2025 →

- प्रदान करने वाली संस्था- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
- इस वर्ष के विजेता-

श्रेणी	इंस्पिरेशन एंड एक्शन	पॉलिसी लीडरशिप	एन्ट्रोप्रेन्योरियल विजन	साइंस एंड इनोवेशन	लाइफटाइम अचीवमेंट
विजेता	सुप्रिया साहू (तमिलनाडु की IAS अधिकारी)	पैसिफिक आइलैंड्स स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज	मरियम इसूफु	इमाजॉन (ब्राजील)	मैनफ्रेडी काल्गाजिरोने

वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड-2025 →

- समारोह- वर्ल्ड एथलेटिक्स मुख्यालय, मोनाको (30 नवंबर 2025)
- प्रमुख पुरस्कार विजेता-

	सर्वश्रेष्ठ एथलीट	राइजिंग स्टार अवार्ड
पुरुष	मोंडो डुप्लांडिस (स्वीडन)	झांग जियाले (चीन)
महिला	सिडनी मैकलॉघलिन (USA)	एडमंड सैरेम (केन्या)

CERAMIC ACADEMY

द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड-2025

- समारोह – दोहा, कतर (16 दिसंबर 2025)
- प्रमुख पुरस्कार विजेता –

	सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी	सर्वश्रेष्ठ कोच	सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर
पुरुष	उस्मान डेम्बले (फ्रांस)	लुइस एनरिक (फ्रांस)	जियानलुइगी डोनारुम्मा (इटली)
महिला	एताना बोनमाती (स्पेन)	सरीना विगमैन (इंग्लैण्ड)	हन्ना हैम्पटन (इंग्लैण्ड)

फीफा फैन अवॉर्ड – आखो एससी (इराक)

ट्रैवल + लेज़र अवार्ड्स-2025

- प्रदानकर्ता संस्था- ट्रैवल + लेज़र इंडिया एंड साउथ इंडिया (लक्ज़री ट्रैवल लाइफस्टाइल पत्रिका)
- समारोह – नई दिल्ली (16 दिसंबर 2025)
- संस्करण – 14 वाँ
- प्रमुख पुरस्कार विजेता –
  1. बेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन – एमिरेट्स एवं सिंगापुर एयरलाइन
  2. बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट – चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर
  3. बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन – एयर इंडिया
  4. बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट – कैम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरू
- राजस्थान के संदर्भ में –
  1. बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन – राजस्थान
  2. बेस्ट लक्ज़री रिसोर्ट (एडिटर्स चॉइस)- द ओबेरॉय राजविलास, जयपुर
  3. बेस्ट लक्ज़री रिसोर्ट - रैफल्स, उदयपुर

अन्य पुरस्कार

- राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM) → संस्कृति मंत्रालय के अधीन संस्था
  - पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया (PRSI) द्वारा दो 'PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार-2025' से सम्मानित किया गया।
  - NCSM की निम्नलिखित दो पहलों को सम्मानित किया –

1. 'हर घर म्यूजियम' पहल	2. 'वैस्ट टू आर्ट' प्रकाशन
कोर्पोरेट अभियान में सोशल मीडिया का सर्वोत्तम उपयोग श्रेणी में	विशिष्ट प्रकाशन श्रेणी में

  - यह पुरस्कार देहरादून (उत्तराखण्ड) में आयोजित 47 वें 'अखिल भारतीय जनसम्पर्क सम्मेलन' में प्रदान किए गए।

- C-DOT → दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केन्द्र
  - इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोनिक इंजीनियर्स (IEEE) के 'IEEE SA कोर्पोरेट पुरस्कार-2025' से सम्मानित।
  - वायरलेस ब्रॉडबैंड, ग्रामीण 5G एवं दूरसंचार शिक्षा में वैश्विक मानकों के विकास हेतु सम्मानित।

CERAMIC ACADEMY

- **संदीप कुमार अग्रवाल** → C-DOT के वैज्ञानिक।
  - 'IEEE SA स्टैंडर्ड्स मैडलियन- 2025' से सम्मानित।
  - ग्रामीण ब्रॉडबैंड मानकों के विकास हेतु सम्मानित।

- **अनंत अंबानी** → 'वंतारा' संरक्षण केन्द्र के संस्थापक।
  - 'ग्लोबल ह्यूमैनिटैरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित होने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के एवं एशिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं।
  - प्रदान करने वाली संस्था- ग्लोबल ह्यूमन सोसायटी

- **नीता अंबानी** → 'ग्लोबल पीस ऑनर- 2025' से सम्मानित।

- **श्री रविशंकर** → 'वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी- 2025' से सम्मानित।

- **शुभम अवस्थी** → सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता
  - नई दिल्ली में आयोजित छठें 'BW लीगल वर्ल्ड' सम्मेलन में '40 अंडर 40 लॉयर अवॉर्ड- 2025' से सम्मानित।
- **नूर इनायत खान** → द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश भारतीय जासूस
  - फ्रांस की राष्ट्रीय डाक सेवा 'ला पोस्ते' ने इनके सम्मान मे स्मारक डाक टिकट जारी किया।

- **वेणु श्रीनिवासन** → TVS मोटर कंपनी के चैयरमैन
  - 'CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार- 2025' से सम्मानित।

- **टॉम क्रूज** → 16 वें गवर्नर्स अवाइर्स में 'मानद ऑस्कर' से सम्मानित।

CERAMIC ACADEMY

खेल समसामयिकी

क्रिकेट (Cricket)

पुरुष अंडर-19 एशिया कप-2025 →

आयोजन	संस्करण	प्रारूप	मेजबान देश	प्रतिभागी टीमें
12-21 दिसंबर	12वाँ	एकदिवसीय (ODI)	संयुक्त अरब अमीरात	8

- प्रशासक – एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC)
- फाइनल – पाकिस्तान V/s भारत (ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई)
  - पाकिस्तान → दूसरी बार विजेता, कप्तान – फरहान युसूफ, स्कोर – 347/8
  - भारत → 191 रन से हारा, कप्तान – आयुष म्हात्रे, स्कोर – 156/10
- समीर मिन्हास (पाकिस्तान) – प्लेयर ऑफ द फाइनल (172 रन की पारी) एवं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट (कुल 471 रन)
- अभिज्ञान कुंडु (भारत)
  ↳ मलेशिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाया (125 गेंदों में 209 रन)

सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी-2025-26 →

आयोजन	प्रशासक	प्रतिभागी टीमें
26 नवंबर-18 दिसंबर	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)	38

- फाइनल – झारखण्ड V/s हरियाणा (पुणे, महाराष्ट्र)
  - झारखण्ड → पहली बार विजेता, कप्तान – ईशान किशन
  - हरियाणा → 69 रन से हारा, कप्तान – अंकित कुमार
- प्लेयर ऑफ द फाइनल – ईशान किशन (झारखण्ड)
- प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट – अनुकूल रॉय (झारखण्ड)

भारत-दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला →

	टेस्ट मैच	एकदिवसीय मैच	T-20 मैच
परिणाम	दक्षिण अफ्रीका 2-0 से जीता	भारत 2-1 से विजेता रहा	भारत 3-1 से विजेता रहा
प्लेयर ऑफ द सीरीज	–	विराट कोहली (302 रन)	वरुण चक्रवर्ती

- इस सीरीज में विराट कोहली ने अपने करियर का 52वाँ शतक (135 रन) बनाया।
- रोहित शर्मा – एकदिवसीय मैचों में सर्वाधिक छक्के (355 छक्के) लगाने का रिकॉर्ड बनाया। पहले यह रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी (351 छक्के) के नाम था।

CERAMIC ACADEMY

भारत–श्रीलंका T-20 श्रृंखला (महिला टीम) →

- आयोजन– विशाखापत्तनम (आंध्रप्रदेश) एवं तिरूवनंतपुरम (केरल)
- परिणाम– भारत 5–0 से विजेता रहा
- प्लेयर ऑफ द फाइनल– हरमनप्रीत कौर
- प्लेयर ऑफ द सीरीज– शैफाली वर्मा

हॉकी (Hockey)

	FIH पुरूष जूनियर हॉकी विश्व कप–2025	FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप–2025
आयोजन	28 नवंबर–10 दिसंबर मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम, चेन्नई एवं मदुरै इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम	1–13 दिसंबर सैंटियागो (चिली)
संस्करण	14 वाँ	11 वाँ
प्रतिभागी टीमें	24 टीमें (6 समूह)	24 टीमें (6 समूह)
फाइनल	जर्मनी V/s इटली ↓ शूटआउट में 3–2 से विजेता आठवीं बार विजेता भारत– तीसरा स्थान (कप्तान–रोहित)	नीदरलैंड V/s अर्जेंटीना ↓ 2–1 से विजेता लगातार तीसरी बार विजेता कुल छठीं बार विजेता भारत–10 वाँ स्थान (कप्तान– ज्योति सिंह)
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी	केस्पर वान डेर वीन (नीदरलैंड)	नूर वैन डेन नियूवेनहोफ (नीदरलैंड)
सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर	जैस्पर डिट्जर (जर्मनी)	मैते बुसेल्स (बेल्जियम)

सुल्तान अजलान शाह कप–2025 →

- आयोजन– अजलान शाह स्टेडियम (मलेशिया) (23–30 नवंबर)
- संस्करण– 31 वाँ
- प्रतिभागी टीमें– 6
- फाइनल– बेल्जियम V/s भारत

  बेल्जियम ↓ 1–0 से विजेता, पहली बार विजेता

  भारत ↓ कप्तान– संजय

स्क्वैश (Squash)

स्क्वैश विश्व कप –2025 →

- आयोजन– चेन्नई (तमिलनाडु) (9–14 दिसंबर)
- फाइनल– भारत V/s हांगकांग (चीन)

  ↓
  3–0 से विजेता
  पहली बार विजेता
  स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला देश बना

CERAMIC ACADEMY

शतरंज (Chess)

FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैम्पियनशिप–2025 →

- आयोजन– दोहा (कतर) (25-31 दिसंबर)
- आयोजक– फेडरेशन इंटरनेशनल डे एचेस (FIDE)

		रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप	ब्लिट्ज शतरंज चैम्पियनशिप
ओपन वर्ग	विजेता	मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे) (छठीं बार)	मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे) (9 वीं बार)
	उपविजेता	व्लादिस्लाव आर्तेमिएव	नोदिरबेक अब्दुसतोरोव
	भारत	अर्जुन एरिगैसी (तीसरा स्थान)	अर्जुन एरिगैसी (तीसरा स्थान)
महिला वर्ग	विजेता	अलेक्जेंड्रा गोरयाचकिना	बिबिसारा असौबायेवा (कजाकिस्तान)
	उपविजेता	झू जिनर (चीन)	अन्ना मुज़िचुक (युक्रेन)
	भारत	कोनेरू हंपी (तीसरा स्थान)	–

निशानेबाजी (Shooting)

ISSF विश्व कप फाइनल–2025 →

- आयोजन– दोहा (कतर) (5-9 दिसंबर)
- आयोजक– इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन (ISSF)
- पदक तालिका–

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	चीन	4	2	3	9
2	भारत	2	3	1	6

भारत के स्वर्ण पदक विजेता–

1. सिमरनप्रीत कौर बराड़ – 25 मीटर पिस्टल (महिला)
2. सुरुचि सिंह – 10 मीटर एयर पिस्टल (महिला)

बैडमिंटन (Badminton)

		BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स–2025	सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप–2025
आयोजन		हांगझू (चीन)	विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश)
संस्करण		–	87वाँ
पुरुष एकल	विजेता	क्रिस्टो पोपोव (फ्रांस)	ऋत्विक संजीवी एस.
	उपविजेता	शी यूकी (चीन)	भरत राघव
महिला एकल	विजेता	ऐन से यंग (द. कोरिया)	सूर्या करिश्मा तामिरी
	उपविजेता	वांग झियी (चीन)	तन्वी पत्री

CERAMIC ACADEMY

अन्य खेल स्पर्द्धाएँ

रोल बॉल विश्व कप–2025 →

- आयोजन– दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)
- आयोजक– इंटरनेशनल रोल बॉल फाउण्डेशन (IRBF)
- संस्करण– 31 वाँ
- फाइनल–

पुरुष वर्ग	महिला वर्ग
भारत v/s केन्या	भारत v/s केन्या
↓	↓
11-10 से विजेता	3-2 से विजेता
पाँचवीं बार विजेता	तीसरी बार विजेता

एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप–2025 →

- आयोजन– ढाका (बांग्लादेश)
- संस्करण– 24 वाँ

भारत– 10 पदक (6 स्वर्ण, 3 रजत एवं 1 कांस्य)

भारत के स्वर्ण पदक विजेता–

1. ज्योति सुरेखा वेन्नम– महिला कंपाउंड स्पर्द्धा
2. धीरज बोम्मदेवरा– पुरुष रिकर्व स्पर्द्धा
3. अंकिता भकत– महिला रिकर्व स्पर्द्धा
4. पुरुष रिकर्व टीम– अतानु दास, राहुल, यशदीप भोगे
5. महिला कंपाउंड टीम– ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीथिका प्रदीप, दीपशिखा
6. मिश्रित टीम– अभिषेक वर्मा, दीपशिखा

चर्चित खिलाड़ी

लेण्डो नॉरिस– मैक्लॉरेन– मर्सिडीज के ड्राइवर

- पहली बार फॉर्मूला वन रेस–2025 का खिताब जीता।
- उपविजेता– मैक्स वेरस्टापेन

सर्वज्ञ सिंह कुशवाह– मध्यप्रदेश

- 3 वर्ष 7 माह 20 दिन की उम्र में 1572 की रैपिड रैटिंग के साथ दुनिया के सबसे कम उम्र के
- FIDE– रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने।
- इन्होंने कलकत्ता के अनीश सरकार (3 वर्ष 8 माह 19 दिन) का रिकॉर्ड तोड़ा।

कैमरून ग्रीन– ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर

- कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के ऑक्शन में ₹25.20 करोड़ में खरीदा।
- ये IPL के इतिहास के सबसे मंहगे खिलाड़ी बने।

CERAMIC ACADEMY

राजस्थान खेल परिदृश्य

सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप–2025→

- आयोजन– वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स
- ओवरऑल रैंकिंग–

रैंक	1	2	3	7
टीम	रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB)	हरियाणा	सर्विसेज (SSCB)	राजस्थान

- राजस्थान के पदक विजेता–

पुरुष फ्रीस्टाइल स्पर्द्धा	महिला फ्रीस्टाइल स्पर्द्धा	ग्रीको रोमन स्पर्द्धा
अनुज कुमार – कांस्य (61 K.g.) राहुल – कांस्य (79K.g.) दीपक – कांस्य (92K.g.)	अंजलि – स्वर्ण (53 K.g.)	अमित चौंधरी – रजत (97 K.g.)

19 वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी→

- आयोजन– लखनऊ (23–29 नवंबर)
- राजस्थान ने स्काउट एवं गाइड दोनों विंग में प्रथम स्थान पर रहा।
- राज्य ने सर्वोच्च पुरस्कार 'चीफ नेशनल कमिश्नर फ्लैग एवं शील्ड' प्राप्त किया।

37 वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैम्पियनशिप→

- आयोजन– लखनऊ
- फाइनल– पंजाब v/s राजस्थान
  ↓
  33–32 से विजेता रही

11 वीं सीएस चैलेंजर ट्रॉफी–2025→

- आयोजन– जयपुर
- इसमें पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया।
  ↳ राजस्थान लेखा सेवा टीम (RACS) v/s भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
  ↓
  24 रन से विजेता
  कप्तान– अपूर्व औशी
- राजस्थान लेखा सेवा महिला टीम → बैडमिंटन – स्वर्ण पदक
  → टेनिस – कांस्य पदक

5 वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैम्पियनशिप→

- आयोजन– मकराना (डीडवाना–कुचामन)

	सीनियर पुरुष वर्ग	सीनियर महिला वर्ग	जूनियर बालक वर्ग	जूनियर बालिका वर्ग	सब–जूनियर बालक वर्ग
स्वर्ण	जयपुर	भीलवाड़ा	जयपुर	नागौर	फलौदी
रजत	फलौदी	जयपुर	फलौदी	बाड़मेर	जयपुर
कांस्य	श्रीगंगानगर	–	श्रीगंगानगर	–	–

CERAMIC ACADEMY

चर्चित खिलाड़ी→

	खिलाड़ी	उपलब्धि
1.	पारूल चौधरी	तमिलनाडु में ऑल इंडिया जूनियर अंडर-19 रैंकिंग बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली राजस्थानी महिला खिलाड़ी बनी।
2.	सुभाष चौधरी (जयपुर)	हांगकांग इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में बॉयज अण्डर-17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
3.	अनुज चौमाल(जयपुर)	बेंगलुरू में आयोजित नेशनल इंडिविजुअल MGFI टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता।
4.	आशी उपाध्याय	बेंगलुरू में आयोजित नेशनल इंडिविजुअल MGFI टूर्नामेंट में रजत पदक जीता।
5.	सुशील मीणा (जयपुर)	नई दिल्ली (करणी सिंह शूटिंग रेंज) में आयोजित छठीं नेशनल पैराशूटिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
6.	गौरव साहू (उदयपुर)	एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप-2025 में 59 कि.ग्रा. भार वर्ग में रजत पदक जीता।
7.	अमनापुरी (जयपुर)	भोपाल में आयोजित 68 वीं नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में 50 मीटर थ्री पॉजिशन सीनियर वर्ग व्यक्तिगत में कांस्य पदक तथा टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
8.	कृष्णा नागर	'ह्यूलिक दाईहत्सू जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप' में दो स्वर्ण पदक जीते।
9.	आराध्या चटर्जी (जयपुर)	दिल्ली में आयोजित 8 वीं नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
10.	अवनि लेखरा	पैराशूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयरराइफल SH-1 स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीता।
11.	कुशाग्र सिंह राजावत (जयपुर)	जापान में आयोजित 25 वें समर डेफलम्पिक्स में निशानेबाजी में 50 मीटर प्रोन स्पर्द्धा में कांस्य पदक जीता।
12.	वैभव प्रताप सिंह (जयपुर)	देहरादून में आयोजित 44वीं नॉर्थ ऑन राइफल शूटिंग चैम्पियनशिप में 50 मीटर थ्री पॉजिशन राइफल स्पर्द्धा में कांस्य पदक जीता।
13.	अमर सिंह देवदा (जयपुर)	थाइलैण्ड में आयोजित 100 कि.मी. इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन में 6 घण्टे 59 मिनट 37 सैकण्ड में दौड़ पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया।
14.	इशिता गुप्ता (जयपुर)	गोवा में आयोजित आयरनमैन 70.3 विश्व चैम्पियनशिप में 1.9 कि.मी. की स्विमिंग, 90 कि.मी. साइकिलिंग एवं 21.1 कि.मी. दौड़ 7 घण्टे 51 मिनट में पूरी कर पहला आयरनमैन खिताब जीता।
15.	पाना देवी गोदारा (गोल्डन दादी)	चेन्नई में आयोजित 23 वीं एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, जैवलिन और डिस्कस थ्रो में चार स्वर्ण पदक जीते।
16.	संस्कार सारस्वत (जोधपुर)	'गुवाहाटी बैडमिंटन मास्टर्स' में मिथुन मंजनाथ को हराकर अपना पहला सुपर-100 खिताब जीता।
17.	रोहित कुमावत	हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता।
18.	गौतम पारीक (जयपुर)	नई दिल्ली में आयोजित नेशनल पैराशूटिंग चैम्पियनशिप में दो पदक जीते- 1. रजत-10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष SH-1 जूनियर स्पर्द्धा 2. कांस्य- 50 मीटर फ्री पिस्टल मिक्सड SH-1 जूनियर स्पर्द्धा
19.	सारिका यादव (जयपुर)	पटना में आयोजित 'अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप' में लॉन्ग जंप स्पर्द्धा में कांस्य पदक जीता। (लगातार तीसरी बार पदक) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हीरापथ मानसरोवर में शिक्षक हैं।
20.	शिक्षा जैन (जयपुर)	मानेसर (हरियाणा) में आयोजित 'US किड्स गोल्फ इंडियन चैम्पियनशिप' का खिताब जीता।

CERAMIC ACADEMY

विविध समसामयिकी

नियुक्तियाँ

❖ **राज कुमार गोयल** → केन्द्रीय सूचना आयोग के 13 वें मुख्य सूचना आयुक्त।
- शपथ – 15 दिसंबर (राष्ट्रपति द्वारा)
- आठ नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी की गई–

1. सुरेन्द्र सिंह मीना 2. आशुतोष चतुर्वेदी 3. स्वागत दास 4. सुधा रानी रैलांगी
5. पी. आर. रमेश 6. खुशवंत सिंह सेंठी 7. जया वर्मा सिन्हा 8. संजीव कुमार जिंदल

❖ **संगीता बरुआ** → प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित।

निधन

❖ **राम वनजी सुथार** → 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' (सरदार वल्लभ भाई पटेल), गुजरात के मूर्तिकार।
- पुरस्कार– पद्म श्री (1999ई.), पद्म भूषण (2016) तथा महाराष्ट्र भूषण।

❖ **विनोद कुमार शुक्ल** → साहित्यकार
- 59 वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार (वर्ष 2024)
- साहित्य अकादमी पुरस्कार (उपन्यास– दीवार में एक खिड़की रहती थी)

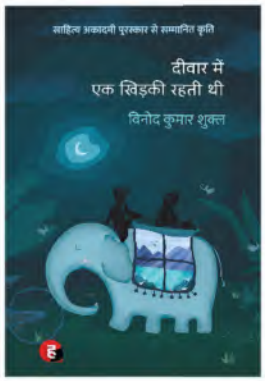

❖ **शिवराज पाटिल** → पूर्व केन्द्रीय रक्षा एवं गृह मंत्री (2004–08)
- 10 वें लोकसभा अध्यक्ष (1991–96)
- पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक (2010–15)

चर्चित पुस्तकें

क्र.स.	पुस्तक	लेखक
1.	द इलेवेंथ ऑवर	सलमान रश्दी
2.	डूइंग द राइट थिंग– लर्निंग्स फ्रॉम रतन टाटा	हरीश भट्ट
3.	सुग्रीवाज एटलस	निलेश ओक
4.	ए सिक्सथ ऑफ ह्यूमनटी	अरविंद सुब्रमण्यम एवं दैवेश कपूर
5.	द ग्रेट सैंक्शन्स हैक	उर्जित पटेल
6.	भारत दैट इज इंडिया	अभिजीत जोग
7.	सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि (उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचन)	वासुदेव देवनानी

CERAMIC ACADEMY

महत्वपूर्ण दिवस

1 दिसंबर	विश्व एड्स दिवस थीम- overcoming disruption, Transforming The AIDS response
3 दिसंबर	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस
7 दिसंबर	सशस्त्र सेना झण्डा दिवस
10 दिसंबर	अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (थीम- Human Rights , Our Everyday Essentials)
14 दिसंबर	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
21 दिसंबर	राष्ट्रीय किसान दिवस (चौधरी चरण सिंह की जयंती)
25 दिसंबर	सुशासन दिवस (अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती)
26 दिसंबर	वीर बाल दिवस

PDF से
नोट्स प्रिन्टिंग
40
पैसा/कॉपी

GARDEN
PHOTO COPY

NEAR SHIV DAIRY, SHIV MANDIR ROAD, RATANADA, JODHPUR - 9928854146

CERAMIC ACADEMY